साांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार
"सच्चे लोगों पर भी उतना ही भरोसा रखिए, जितनी दवाईयों पर रखते हैं, बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर फायदेमंद ही होंगे ...!!"
अज्ञात...

वर्ष-01 अंक-173 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, रविवार 12 जुलाई 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य -2 रुपए

छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस चुनाव : महंत-बाबा खेमे से शैलेंद्र बंजारे तय, भूपेश खेमे में अभी संशय

स्क्रूटनी में फंस सकते हैं कई दिग्गज, उम्र और अपराधिक रिकॉर्ड पर दर्जनों आपत्तियां, भूपेश बघेल के पंजाब से लौटते ही समर्थकों में उत्साह

आलोक तिवारी / रायपुर

छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक ओर महंत-बाबा खेमे से उम्मीदवार तय माने जा रहे हैं, तो वहीं भूपेश खेमे में अभी पत्ते नहीं खुले हैं। नामांकन के बाद शुरू हुई स्क्रूटनी में कई बड़े नामों के बाहर होने की आशंका से दोनों खेमों में बेचैनी है।

महंत-बाबा खेमे से शैलेंद्र बंजारे की दावेदारी पक्की : सूत्रों के अनुसार महंत-बाबा खेमे से शैलेंद्र बंजारे का नाम लगभग तय हो चुका है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला खेलकर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बाबा और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत का आशीर्वाद शैलेंद्र बंजारे के लिए जुटा लिया है। देवेंद्र यादव से सेक्टर पांच भिलाई निवास में शैलेंद्र बंजारे ने मुलाकात कर चुनावी शंखनाद पहले ही कर चुके है। देवेंद्र यादव का पूरा संरक्षण होने की वजह से शैलेन्द्र बंजारे रेस में अभी तक सिंगल घोड़े की तरह है।

भूपेश खेमे में असमंजस, 3 नाम दौड़ में : वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल के खेमे में अभी तस्वीर साफ नहीं है। भूपेश बघेल आज ही पंजाब से लौटे हैं। उनके लौटने से समथर्कों में नया उत्साह है। सूत्रों का कहना है कि भूपेश बघेल समर्थकों से पूरी जानकारी लेकर परिस्थितियों को समझने के बाद ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेंगे।

भूपेश खेमे से सत्येंद्र चेलक का नाम सबसे आगे चल रहा है और उन्हें फाइनल माना जा रहा है। लेकिन उनके अलावा जसमीत सोनू शर्मा और प्रशांत बोकाड़े भी दौड़ में हैं। जब तक भूपेश बघेल सार्वजनिक रूप से नाम घोषित नहीं करते, तब तक सभी दावेदार जोर-आजमाइश में जुटे हुए हैं।

स्क्रूटनी में फंसेंगे कई बड़े नाम : युवा कांग्रेस चुनाव में सबसे बड़ा पेंच स्क्रूटनी का है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश एवं जिला अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोक चुके कई उम्मीदवारों की उम्र और आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

राष्ट्रीय युवा कांग्रेस को दर्जनों आपत्तियां मिली हैं। कुछ दावेदारों की ओवर एज के ठोस सबूत भी दिए गए हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि स्क्रूटनी के बाद बहुत से उम्मीदवार मैदान से बाहर हो जाएंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ दावेदारों ने नामांकन के दौरान अपने आपराधिक प्रकरण छिपाए हैं। युवा कांग्रेस के कड़े नियमों में अपराधिक जानकारी छुपाने पर नाम खारिज करने का प्रावधान है। ऐसे उम्मीदवारों का भविष्य भी स्क्रूटनी से तय होगा।

जिनके खिलाफ अंतिम तिथि 8 जुलाई तक आपत्ति नहीं लग सकी, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई है। ऐसे में वे चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन उनका परिणाम तब तक रोका जाएगा जब तक वे साबित नहीं कर देते कि आपत्तियां निराधार हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर से हजारों उम्मीदवारों ने ब्लॉक से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के पदों के लिए नामांकन भरा है। स्क्रूटनी के बाद ही चुनाव योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुनाव का शंखनाद होगा।

भाजपा ले रही मजा, बोली- कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई : युवा कांग्रेस के चुनाव के बीच भाजपा नेताओं ने भी बयानबाजी शुरू कर दी है। भाजपा नेता युवा कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बता रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों खेमों को अब स्क्रूटनी रिपोर्ट का इंतजार है। स्क्रूटनी के बाद ही साफ होगा कि युवा कांग्रेस में दो चेहरों के बीच महासंग्राम किसके बीच होगा।

बीएसपी की ब्लास्ट फर्नेस-8 महामाया ने रचा इतिहास

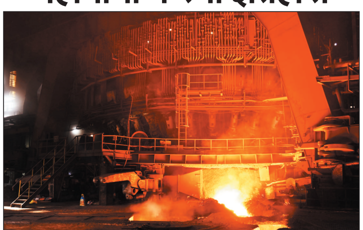

सिर्फ 3080 दिनों में 21 मिलियन टन हॉट मेटल उत्पादन का कीर्तिमान

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र की सबसे बड़ी और आधुनिक ब्लास्ट फर्नेस-8 महामाया ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। फर्नेस ने 10 जुलाई 2026 को अपने अभियान के दौरान 21 मिलियन टन संचयी हॉट मेटल उत्पादन का महत्वपूर्ण माइलस्टोन पार कर लिया।

3080 दिनों में हासिल किया ऐतिहासिक लक्ष्य

2 फरवरी 2018 को कमीशन की गई महामाया ने यह उपलब्धि मात्र 3080 दिनों में हासिल कर भारतीय इस्पात उद्योग में नया मानदंड स्थापित किया है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि फर्नेस ने 20 मिलियन टन से 21 मिलियन टन तक का सफर सिर्फ 121 दिनों में पूरा किया। यह इसकी उत्कृष्ट परिचालन क्षमता, उच्च तकनीकी दक्षता और अधिकारियों-कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों का प्रमाण है।

प्रबंधन ने टीम को दी बधाई

इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर भिलाई इस्पात संयंत्र के शीर्ष प्रबंधन ने ब्लास्ट फर्नेस-8 की पूरी टीम को बधाई दी है। प्रबंधन ने टीम के समर्पण, तकनीकी दक्षता और उत्कृष्ट टीमवर्क की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की उपलब्धियां ही बीएसपी को देश का सबसे भरोसेमंद इस्पात संयंत्र बनाती हैं।

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इतने कम समय में 21 मिलियन टन उत्पादन का आंकड़ा छूना महामाया की विश्वस्तरीय क्षमता को दर्शाता है और आने वाले समय में बीएसपी के उत्पादन लक्ष्य हासिल करने में यह मील का पत्थर साबित होगा।

20 से 21 मिलियन टन का सफर महज 121 दिन में पूरा किया

बीएसपी की रीढ़ बनी महामाया

ब्लास्ट फर्नेस-8 महामाया भिलाई इस्पात संयंत्र के हॉट मेटल उत्पादन में रीढ़ की भूमिका निभा रही है। अत्याधुनिक तकनीक, सुव्यवस्थित परिचालन, प्रभावी रखरखाव और सुरक्षित कार्य संस्कृति के बल पर यह विभाग लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर इस्पात निर्माण प्रक्रिया की समग्र दक्षता को सुदृढ़ कर रहा है।

बीएसपी स्क्रैप चोरी का काला कारोबार : फ्लू डस्ट ठेके की सिफारिश तक पहुंचेगी जांच

पूरे सिंडिकेट को तोड़ने में जुटी दुर्ग जिला पुलिस की विशेष टीम

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई-दुर्ग

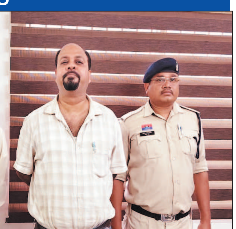

बीएसपी से 250 टन लौह स्क्रैप चोरी के बहुचर्चित मामले में पुलिस अब सिर्फ चोरों तक नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की तैयारी में है। जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब फ्लू डस्ट परिवहन ठेका किसकी सिफारिश पर मिला और इस काले कारोबार को किसका संरक्षण प्राप्त था, इसे भी खंगाला जा रहा है।

250 टन स्क्रैप बरामदगी के बाद 15 गिरफ्तार

26 मई को भिलाई के अकलोरडीह स्थित एके ट्रेडर्स के गोदाम से 250 टन बीएसपी स्क्रैप बरामद होने के बाद शुरू हुई कार्रवाई में अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार लोगों में बीएसपी के जीएम हिमांशु भूषण मलिक और इंजीनियरिंग एसोसिएट मनोज देवांगन के साथ कई ट्रांसपोर्टर भी शामिल हैं।

पुलिस अब बीएसपी और सीआईएसएफ के उन अधिकारी-कर्मचारियों की भूमिका भी जांच रही है, जिनकी ड्यूटी के दौरान पिछले कई महीनों से स्क्रैप चोरी का सिलसिला चलता रहा।

ठेका सिफारिश और 60 ट्रकों को कटवाने की जांच

पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच का फोकस अब केवल चोरी तक सीमित नहीं है। यह पता लगाया जा रहा है कि फ्लू डस्ट के ठेके के लिए किसने सिफारिश की और इस प्रक्रिया से किन प्रभावशाली लोगों को लाभ मिला।

जांच में यह भी सामने आया है कि कार्रवाई शुरू होते ही रायपुर के चंदनडीह स्थित यार्ड में करीब 60 संदिग्ध ट्रकों को कटवा दिया गया। पुलिस यह पता कर रही है कि ये ट्रक वैधानिक प्रक्रिया से कबाड़ हुए या जांच से बचने के लिए जल्दबाजी में काटे गए।

इसी कड़ी में पुलिस ने दुर्ग के रसमड़ा और रायपुर के सिलतरा स्थित कुछ औद्योगिक इकाइयों में दबिश दी है, जहां चोरी का स्क्रैप खपाए जाने की आशंका है। कई जगह इकाइयां बंद मिलीं। स्क्रैप कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि चोरी का माल बंद होने से ट्रांसपोर्ट नगर की करीब 10 इकाइयों का संचालन ठप हो गया है।

जनप्रतिनिधियों से कनेक्शन की पड़ताल

जांच में एक अहम खुलासा यह भी हुआ है कि कुछ आरोपी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संपर्क में थे। पुलिस यह पता लगा रही है कि इन मुलाकातों का संबंध स्क्रैप परिवहन और ठेका प्रक्रिया से था या नहीं। सूत्रों के अनुसार एक जनप्रतिनिधि के निजी सहयोगी के जरिए संपर्क साधे जाने की जानकारी भी मिली है।

36 दिन बाद भी फरार

इस बड़े नेटवर्क का एक मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। 36 दिन बीत जाने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

बीएसपी से चोरी का स्क्रैप खरीदने वालों का भी बन रही है सूची

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 250 टन स्क्रैप बरामद होने के बाद पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बीएसपी के जीएम व एजीएम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। स्क्रैप चोरी के कालाबाजारी में चोरी करने वाले को लगभग पुलिस के सामने बेनकाब हो चुके हैं। पुलिस अब उन लोगों की सूची तैयार कर रही है जो लोहा चोरों से चोरी का सामान बड़े पैमाने पर खरीददते थे। सूत्रों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने सिलतरा, रसमड़ा, उरला और रायपुर के कई बड़े कारखानों के मालिकों को सूचीबद्ध किया है जो चोरी का लोहा खरीदते थे। यहां उल्लेखनीय है कि चोरी करना तो अपराध है ही, चोरी का माल खरीदना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है।

जुटाए जा रहे हैं साक्ष्य

एएसपी शहर दुर्ग सुखनंदन राठौर ने बताया, "मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए हर पहलू से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।" अब पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़कर काला कारोबार चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है।

एकतरफा प्रेम में युवती की हत्या, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

धारदार हथियार और मोटरसाइकिल बरामद, साक्ष्य मिटाने की कोशिश भी नाकाम

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई-दुर्ग

वैशाली नगर थाना क्षेत्र में एकतरफा प्रेम प्रसंग में किराये के कमरे में रह रही युवती की हत्या करने वाले आरोपी को दुर्ग पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।

पुलिस के अनुसार 10 जुलाई को दोपहर लगभग 12 बजे मृतिका खुशी साहू की रूममेट ने परिजनों को सूचना दी कि खुशी कमरे में खून से लथपथ और गंभीर रूप से घायल पड़ी है। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर थाना वैशाली नगर में अपराध क्रमांक 285/2026, धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

इस तरह दी घटना को अंजाम

पूछताछ में आरोपी लाकेश्वर साहू उर्फ पिंटू, 24 वर्ष, निवासी सकरी, बलौदाबाजार ने अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी मृतिका से एकतरफा प्रेम करता था। युवती द्वारा बात न करने पर उसने पूर्व नियोजित योजना बनाकर रायपुर से भिलाई आकर हत्या की।

आरोपी पहचान छिपाने के लिए दो शर्ट और पैंट के अंदर बरमूडा पहनकर आया था। कमरे में विवाद के बाद उसने पहले युवती का गला दबाया और फिर धारदार हथियार से शरीर पर कई वार कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने कपड़े और जूते नदी में फेंककर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया।

24 घंटे में हुई गिरफ्तारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना वैशाली नगर पुलिस और एसीयू टीम ने तकनीकी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी को 11 जुलाई को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने आरोपी से हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की है। प्रकरण में धारा 103(1) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

एक बार फिर भिलाई में 17 से 23 अगस्त तक होगी शिवमहापुराण कथा

पंडित प्रदीप मिश्रा सुनाएंगे कथा, 16 अगस्त को निकलेगी भव्य कलश यात्रा, लगातार तीसरी बार आयोजन, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

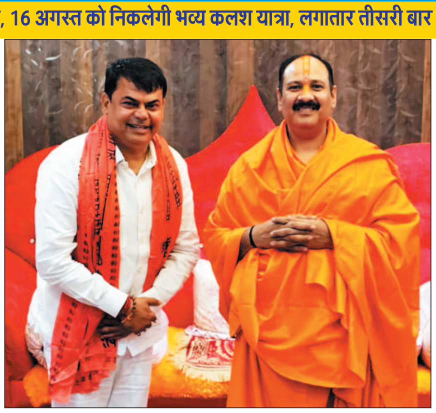

सावन के पावन महीने में भिलाई एक बार फिर भक्ति के रंग में रंगेगा। बोल बम सेवा कल्याण समिति द्वारा आयोजित शिवमहापुराण कथा इस बार लगातार तीसरी बार होगी। आयोजन समिति ने इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने का लक्ष्य रखा है।

कथा 17 अगस्त से 23 अगस्त 2026 तक जयंती स्टेडियम, सिविक सेंटर में प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक होगी। कथा वाचन पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी सरल शैली में करेंगे। आयोजन के संयोजक समिति अध्यक्ष एवं पार्षद दया सिंह हैं।

16 अगस्त को निकलेगी भव्य कलश यात्रा : कथा से पूर्व 16 अगस्त को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा सेक्टर-5 स्थित गणेश मंदिर से दोपहर में प्रारंभ होकर विभिन्न चौक-चौराहों से होते हुए जयंती स्टेडियम पहुंचेगी। दया सिंह ने बताया कि यात्रा को भव्य रूप दिया जाएगा। मार्ग में हर चौक-चौराहे पर भगवान शिव के अलग-अलग स्वरूपों की झांकियां सजेंगी। कहीं शिव विवाह, कहीं ओघड़दानी रूप, तो कहीं विषपान करते शिव के दर्शन होंगे। कलश यात्रा में हरियाणा और मध्य प्रदेश की विशेष झांकियां के साथ ही हनुमान, गणेश और नंदी की आकर्षक प्रस्तुतियां भी शामिल होंगी। जगह-जगह भक्त कलश यात्रा का स्वागत करेंगे।

17 अगस्त नागपंचमी से कथा का शुभारंभ : शिवमहापुराण कथा का शुभारंभ 17 अगस्त सोमवार, नागपंचमी के शुभ अवसर पर होगा। कथा प्रतिदिन जयंती स्टेडियम में दोपहर 1 से 4 बजे तक होगी। आयोजन के लिए बीएसपी से जयंती स्टेडियम की अनुमति मिल चुकी है। पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा सार्वजनिक घोषणा के बाद प्रशासन के साथ बैठक का दौर जल्द शुरू होगा।

छत्तीसगढ़-एमपी का सबसे बड़ा पंडाल : इस बार आयोजन को और भव्य बनाने के लिए जयंती स्टेडियम में 5 बड़े पंडाल लगाए जाएंगे। इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी पंडाल बनाए जाएंगे। आयोजकों का दावा है कि यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पंडाल होगा। कथा के दौरान पूरे दिन श्रद्धालुओं के लिए भोजन-प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी। आयोजन में प्रदेश के प्रमुख नेता और अतिथि भी शामिल होंगे। जल्द ही भूमि पूजन की तिथि की घोषणा की जाएगी।

लगातार तीसरी बार, बनेगा रिकॉर्ड : बोल बम सेवा कल्याण समिति द्वारा सावन में लगातार तीसरी बार एक ही स्थान पर इतने बड़े स्तर पर कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कारण इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी है।

समिति ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे परिवार सहित इस दिव्य आयोजन में शामिल होकर शिव कृपा प्राप्त करें।

विधायक चंद्राकर ने डुंडेरा वार्ड 35 व 36 में 1 करोड़ 25 लाख के विकास कार्यों की रखी आधारशिला

यादव समाज और साहू समाज भवन की बहुप्रतीक्षित मांग हुई पूरी, विधायक ललित चंद्राकर ने कहा – मोदी की गारंटी से गांव का हो रहा है कायाकल्प

नई दृष्टिबिंदु / रिसाली-भिलाई

डबल इंजन की सरकार में क्षेत्र के चहुमुखी विकास को नई गति मिल रही है। इसी क्रम में आज रिसाली नगर निगम अंतर्गत ग्राम डुंडेरा के वार्ड क्रमांक 35 एवं 36 में लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण एवं भूमिपूजन कर आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने विधिवत पूजा-अचर्ना कर नवीन विकास कार्यो का शुभारंभ किया। इन कार्यों में यादव समाज सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रुपये एवं साहू समाज भवन के लिए 10 लाख रुपये की राशि भी शामिल है।

इस अवसर पर विधायक ललित चंद्राकर ने अपने संबोधन में कहा किह्वआज साहू समाज और यादव समाज के भवन की जो मांग वर्षों से थी, वह आज पूरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज के हर वर्ग के सम्मान और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं।

रिसाली क्षेत्र में सड़क, नाली, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ सामुदायिक भवनों के निर्माण से सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा। हमारी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही हमारा संकल्प है। हमारा प्रयास है कि दुर्ग ग्रामीण का हर गांव, हर वार्ड विकास की मुख्य धारा से जुड़े।

आगे श्री चंद्राकर ने कहा कि डबल इंजन की सरकार गरीब कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को पक्का मकान मिल रहा है। महतारी वंदन योजना से प्रदेश की 70 लाख से अधिक माताओं-बहनों के खाते में हर महीने 1000 रुपये आ रहे हैं। कृषक उन्नति योजना से किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का बोनस मिल रहा है। तीर्थ दर्शन योजना से बुजुर्ग माताएं-पिता अयोध्या और अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। ये सभी योजनाएं मोदी जी की गारंटी हैं और विष्णु सरकार इन्हें जमीन पर उतारने का काम कर रही है।

इस अवसर पर प्रमुख रूप से रिसाली नगर निगम महापौर शशि सिन्हा, जिला भाजपा मंत्री शैलेन्द्र शेंडे, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजू राकेश जंघेल, विधायक प्रतिनिधि गोविन्द साहू, नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू, पार्षद विक्की खिलेन्द्र चंद्राकर, रोहित धनकर, सरिता देवांगन, ईश्वरी सिन्हा, ममता सिन्हा, महामंत्री नरेन्द्र निर्मलकर, महिला मोर्चा अध्यक्ष शिखा तिवारी, मंडल मंत्री इंद्रजीत सोनी, रंजन सिंहा, मंडल उपाध्यक्ष राजू राम, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता एम. लक्ष्मण राव, डी. साईं, बूथ अध्यक्ष परमेश्वर, देवेन्द्र साहू, हर्ष चंद्राकर, रंजना मानिकपुरी, देवेश साहू, डॉ. पावर्ती कुर्रे, दुर्गेश साहू, अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल अध्यक्ष केशव महिपाल, नारायण निर्मलकर, योगेश महिपाल, साहू समाज अध्यक्ष संजय साहू, यादव समाज अध्यक्ष मोहन लाल यादव, खेमलाल साहू, गायत्री यादव, देवेन्द्र साहू, नंदकुमार, विकास साहू, हरीश नायक सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

खास खबर

सर्व समाज कल्याण समिति ने कहा – "पुस्तकें सपनों को देती हैं एक नई उड़ान"

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

जरूरतमंद विद्यार्थियों को बांटी कक्षा 11वीं की पुस्तकें

सर्व समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह "छोटू भैया" के नेतृत्व में गुरुवार को आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं की अध्ययन सामग्री वितरित की गई। इस दौरान जरूरतमंद छात्रों को पुस्तकें प्रदान कर उनके उज्वल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम में अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह "छोटू भैया" ने कहा कि समिति का उद्देश्य है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र केवल आर्थिक अभाव के कारण अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। शिक्षा के क्षेत्र में यह छोटा-सा प्रयास आने वाले कल को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा, "पुस्तकें सिर्फ ज्ञान नहीं देतीं, बल्कि सपनों को उड़ान भी देती हैं।" समाज के हर वर्ग तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना ही हमारी प्राथमिकता है। सर्व समाज कल्याण समिति ने संकल्प लिया कि वह शिक्षा, सेवा और समाज के विकास के लिए सदैव समर्पित रहेगी। समिति आगे भी जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक और समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बीएसपी : एसएमएस-3 ने 96 दिनों में पूरा किया 21 मिलियन टन का लक्ष्य, उत्पादन में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, SAIL के लक्ष्यों में अहम योगदान

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप-3 ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। स्टर-3 ने 10 जुलाई 2026 को 21 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित किया।

96 दिनों में पूरा हुआ 20 से 21 मिलियन टन का सफर : SMS-3 ने 20वें मिलियन टन से 21वें मिलियन टन तक का उत्पादन सिर्फ 96 दिनों में पूरा किया। यह शॉप का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले इतनी तेज गति 16वें मिलियन टन के दौरान दर्ज की गई थी। अब तक का सबसे तेज प्रदर्शन 20वां मिलियन टन रहा था, जिसे 19वें मिलियन टन की तिथि 5 अप्रैल 2026 से 92 दिनों में पूरा किया गया था।

समर्पण और तकनीकी दक्षता का प्रमाण : यह लगातार तेज गति वाला प्रदर्शन स्टर-3 की पूरी टीम के समर्पण, सुदृढ़ प्रक्रिया नियंत्रण, बेहतर उपकरण विश्वसनीयता और केंद्रित परिचालन पद्धतियों का नतीजा है। 100 दिनों से कम समय में कई मिलियन टन के मील के पत्थर पार करना उत्पादकता, सुरक्षा और इस्पात निर्माण में उत्कृष्टता के प्रति एसएमएस-3 की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

SAIL के उत्पादन लक्ष्यों में अहम भूमिका : इस उपलब्धि के साथ एसएमएस-3 ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए SAIL के समग्र उत्पादन लक्ष्यों में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सीजीएम, एसएमएस-3 त्रिभुवन बैठा ने पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने इस गति को बनाए रखने और संयंत्र के लिए नए मानक स्थापित करने में सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, संविदा सहयोगियों और सभी संबद्ध विभागों के योगदान की सराहना की।

" पीएम मोदी की गारंटी" चुनावी जुमला निकली, प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चरमराई : अरुण वोरा

11 दिनों से हड़ताल पर अतिथि शिक्षक, नियमितीकरण नहीं तो आंदोलन और तेज होगा – शिक्षकों की चेतावनी

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग-रायपुर

प्रदेशभर के अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आंदोलन के कारण सरकारी स्कूलों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो गई है, लेकिन सरकार अब भी मौन है। इस बीच पूर्व विधायक अरुण वोरा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को "मोदी की गारंटी" बताकर जनता से वादे किए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद उन वादों को पूरा नहीं किया गया।

100 दिन का वादा अधूरा

वोरा ने कहा, "घोषणा पत्र में कहा गया था कि सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर अतिथि, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कमर्चारियों के नियमितीकरण के लिए समिति का गठन होगा। लेकिन आज तक यह वादा अधूरा है।" उन्होंने आंदोलन स्थल पर शिक्षकों का समर्थन करते हुए कहा, "मोदी की गारंटी अब केवल चुनावी जुमला साबित हुई है। सरकार को अपने वादे निभाने होंगे और अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करना होगा।"

स्कूलों में पठन-पाठन ठप

आंदोलनकारियों का कहना है कि वर्षों से सरकारी स्कूलों में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों को सिर्फ आश्वासन मिले हैं। लगातार 11 दिनों से चल रहे आंदोलन से प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था ध्वस्त हो गई है।

आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार पाली, राकेश यादव और प्रदेश सचिव सुधीर चंदेल ने भी शिक्षकों की मांगों को जायज बताते हुए सरकार से तत्काल नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की।

"नियमितीकरण नहीं तो आंदोलन तेज"

शिक्षकों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक नियमितीकरण पर ठोस और लिखित निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने नारा दिया – "वादा किया है तो निभाना होगा, अतिथि शिक्षकों को उनका अधिकार दिलाना होगा... वरना गद्दी छोड़नी होगी!" नेताओं ने कहा कि यदि सरकार जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लेती तो आंदोलन को और व्यापक जनसमर्थन दिया जाएगा।

IIIE भिलाई चैप्टर के काउंसिल सदस्य विजय सराफ का निधन

माइनिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति, इंजीनियरों ने दी श्रद्धांजलि

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स, भिलाई चैप्टर के काउंसिल सदस्य और प्रख्यात माइनिंग एवं इंडस्ट्रियल इंजीनियर विजय कुमार सराफ का निधन हो गया है। उनके निधन को संस्था और इंजीनियरिंग जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है। भिलाई चैप्टर ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विशिष्ट योगदान को सराहा।

सरल व्यक्तित्व और समर्पण के धनी थे सराफ

श्री सराफ एक कुशल, अनुभवी एवं अत्यंत सम्मानित अभियंता थे। उन्होंने माइनिंग एवं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने के साथ-साथ आईआईआईई भिलाई चैप्टर की गतिविधियों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका अनुभव, कार्यनिष्ठा, सरल व्यक्तित्व और संस्थान के प्रति समर्पण सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा।

पदाधिकारियों ने जताया शोक

श्री सराफ के निधन पर चेयरमैन के. पटेल, वाइस चेयरमैन घनश्याम कुमार देवांगन, सेक्रेटरी अवनिश दुबे, ट्रेजरार विवेक गुप्ता, एक्स चेयरमैन एच. के. देसाई, बीएसपी के पूर्व सीईओ वी.के. अरोरा, पूर्व जीएम एल. के. वैद्यनाथन सहित समस्त पदाधिकारियों, काउंसिल सदस्यों और सदस्यों ने गहरा शोक व्यक्त किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि श्री सराफ का योगदान सदैव सम्मान और कृतज्ञता के साथ स्मरण किया जाएगा।

परिवार के प्रति संवेदना

आईआईआईई भिलाई चैप्टर की ओर से उनके सुपुत्र आदित्य सराफ तथा समस्त शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की गई है। संस्था ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें और शोक-संतप्त परिवार को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति दें।

केएच मेमोरियल स्कूल में इंस्टीट्यूट सेरेमनी 2026-27 का हुआ भव्य आयोजन

छात्र परिषद को मिली जिम्मेदारियां, तेजस हेड बॉय और दीप्ति बनी हेड गर्ल

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

जवाहर नगर स्थित केएच मेमोरियल स्कूल में नेतृत्व, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के उद्देश्य से Institute Ceremony 2026-27 का भव्य एवं गरिमामय आयोजन किया गया। समारोह में नवनिर्वाचित छात्र परिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाकर बैज एवं सैश पहनाए गए।

दीप प्रज्वलन से हुई शुरुआत : कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यार्थियों के स्वागत गीत से हुआ। इसके बाद मुख्य अतिथि भिलाई नगर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी, प्राचार्य विभा झा, डायरेक्टर निश्चय झा और अकादमी डायरेक्टर सृष्टि झा का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया गया। सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया।

अनुशासन और परिश्रम का दिया संदेश : प्राचार्य विभा झा ने विद्यार्थियों को अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और नेतृत्व के महत्व से अवगत कराया। मुख्य अतिथि सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से ही जीवन में सफलता मिलती है। उन्होंने विद्यार्थियों से गुरुजनों और माता-पिता का सम्मान करने की अपील की। साथ ही कहा कि नई शिक्षा व्यवस्था में भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और संस्कारों का समावेश जरूरी है। अनुशासन, सेवा भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास ही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। डायरेक्टर निश्चय झा ने कहा कि नेतृत्व का अवसर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। वहीं अकादमी डायरेक्टर सृष्टि झा ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ खेल, संस्कृति और सामाजिक गतिविधियों में भी उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया।

इन्हें मिली जिम्मेदारियां : बैज एवं सैश वितरण समारोह में इस वर्ष तेजस मारिया को हेड बॉय और दीप्ति यादव को हेड गर्ल घोषित किया गया। आर्यन वर्मा वाइस हेड बॉय और शास्कारी चंदोरे वाइस हेड गर्ल बनीं।

इसके अलावा विभिन्न हाउस प्रीफेक्ट, असिस्टेंट हाउस प्रीफेक्ट, स्पोर्ट्स प्रीफेक्ट, कल्चरल प्रीफेक्ट, लिटरेरी क्लब प्रीफेक्ट, ईको क्लब एवं डिसिप्लिनरी प्रीफेक्ट सहित कई छात्र-छात्राओं को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। समारोह के दौरान मिडिल विंग के विद्यार्थियों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। अंत में हेड बॉय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

आज शाम को 'आरंभ' की आठवीं सांगठनिक बैठक और 'भिलाई जिंदाबाद' पर समीक्षा गोष्ठी का आयोजन

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

प्रगतिशील जन-विचारधारा की साहित्यिक संस्था 'आरंभ' के तत्वावधान में दो सत्रों में सांगठनिक बैठक और समीक्षा गोष्ठी का आयोजन 12 जुलाई रविवार को किया गया है। अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य ने बताया कि प्रथम सत्र अपराह्न 3 बजे से 4.30 बजे तक आठवीं सांगठनिक बैठक एवं खुला सत्र आयोजित है। जिसमें प्रतिवेदन/संचालन महासचिव नुरूसबाह खान 'सबा' करेंगी। इस सत्र में नियमावली पर विस्तृत जानकारी ठाकुर दशरथ सिंह भुवाल सोनपांडर देंगे। उपस्थित आजीवन/संस्थापक सदस्यों द्वारा दिए गए विचार/सुझाव के बाद 'आरंभ' के मुख्य सलाहकार आचार्य डॉ. महेश चंद्र शर्मा का उद्बोधन होगा। प्रथम सत्र का धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्षा दीप्ति श्रीवास्तव देंगी।

द्वितीय सत्र में शाम 4.30 से 6.30 बजे तक पत्रकार-लेखक मुहम्मद जाकिर हुसैन की कृति 'भिलाई जिंदाबाद कुछ किस्से-कुछ कहानियां' पर चर्चा गोष्ठी रखी गई है। इस चर्चा गोष्ठी के मुख्य अतिथि भिलाई इस्पात संयंत्र ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया (सेफी) के चेयरमैन नरेंद्र कुमार बंछोर और मुख्य वक्ता सुपरिचित पत्रकार/लेखक/कवि एवं एनडीटीवी के संवाददाता निलेश त्रिपाठी होंगे।'

आरंभ' के मुख्य सलाहकार व संस्कृत विद्वान आचार्य डॉ. महेशचंद्र शर्मा इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हिंदी व्यंग्य के सुस्थापित लेखक विनोद साव और स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. हंसा शुक्ला विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। सरस्वती वंदना संध्या साटकर प्रस्तुत करेंगी। स्वागत उद्बोधन 'आरंभ' के अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य, संचालन महासचिव नुरूस्सबाह खान 'सबा' और आभार व्यक्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रयम्बक राव साटकर 'अंबर' देंगे। ये जानकारी प्रवक्ता जाविद हसन 'भाईजान'ने दी।

राम गोपाल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

भिलाई में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री साय का पुतला फूंका, पुलिस से हुई धक्का-मुक्की

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम गोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में शनिवार को भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने मैत्री गार्डन चौक रिसाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने किया।

जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप : कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार केंद्रीय एवं राज्य की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेताओं को निशाना बना रही है। इसी विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बीजेपी मुर्दाबाद के बैनर और पोस्टर लेकर रैली निकाली और चौक पर पहुंचकर नारेबाजी की।

पुलिस से हुई झड़प : पुतला दहन को देखते हुए पहले से भारी पुलिस बल तैनात था। पुलिस ने कांग्रेसियों के हाथ से पुतला छीनने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई।

आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद कांग्रेसियों ने दोनों पुतलों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने जलते पुतलों को छीनने का प्रयास किया और बाद में पानी डालकर आग बुझाई।

सैकड़ों कार्यकर्ता रहे शामिल : इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, अकऊउ सदस्य, विधायक, पूर्व विधायक, महापौर, पूर्व महापौर, सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, ठरवक् अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश पटेल, जी राजू, नर्सिंग नाथ, सौरभ मिश्रा, गिरवर साहू, रविंद्र सिंह समेत बड़ी संख्या में पार्षद, पूर्व पार्षद, जोन अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष भी प्रदर्शन में शामिल हुए।

ग्रामीण विकास से जुड़े पंचायत के सभी कार्यों में गुणवत्ता हो सर्वोच्च प्राथमिकता – उप मुख्यमंत्री शर्मा

हर स्कूल में बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शौचालय निर्माण के निर्देश, वीबी जीरामजी के प्रभावी क्रियान्वयन पर जिला पंचायत सीईओ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने कहा ग्रामीण विकास से जुड़े सभी कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को कमर कसकर अगले आठ महीनों में निर्धारित सभी लक्ष्यों को तेजी और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित महानदी भवन में वीबी जीरामजी योजना एवं पंचायत विभाग के विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) से जुड़े।

जिला पंचायत सीईओ को विकासखंडों का करें नियमित भ्रमण : उप मुख्यमंत्री ने सभी जिला पंचायत सीईओ को अपने-अपने विकासखंडों का नियमित भ्रमण करने, निर्माण कार्यों की सतत निगरानी रखने तथा आमजन की शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए मैदानी स्तर पर सक्रियता और जवाबदेही आवश्यक है।

मुक्तिधाम एवं इंजेक्शन वेल का प्राथमिकता से करें निर्माण : उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी स्कूलों में बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शौचालयों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कर शत-प्रतिशत संतृप्तता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन ग्रामों में मुक्तिधाम उपलब्ध नहीं हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर मुक्तिधाम निर्माण कराने तथा अनुपयोगी एवं खराब पड़े बोरवेलों को इंजेक्शन वेल के रूप में विकसित कर जल संरक्षण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

वीबी जीरामजी के कार्यों में पारदर्शिता एवं एसओपी का हो पालन : वीबी जीरामजी योजना की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय, वरिष्ठ नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने, विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से विकास कार्यों को गति देने तथा सभी कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वीबी जीरामजी योजना का लाभ तेजी से प्रत्येक ग्राम तक पहुंचना चाहिए। मंत्री श्री शर्मा ने वीबी जीरामजी के अंतर्गत धान खरीदी केन्द्रों में चबूतरों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पीएम श्री विद्यालयों, पोटा केबिनों एवं अन्य विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण एवं शौचालय निर्माण, धरसा विकास जैसे जनहितकारी कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

गरीब परिवारों के आवास निर्माण में बाधा उत्पन्न करने पर दण्डात्मक कार्रवाई: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए श्री शर्मा ने सभी निर्माण कार्यों की समयबद्ध जियो-टैगिंग कराने तथा नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि गरीब परिवारों के आवास निर्माण में यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी अनावश्यक बाधा उत्पन्न करता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।

जिम्मेदारी, पारदर्शिता, संवेदनशीलता के साथ अधिकारी करें कार्य : उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि गांवों में स्थायी और गुणवत्तापूर्ण विकास सुनिश्चित करना है। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी पूरी जिम्मेदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ समय पर आम नागरिकों तक पहुंचे। उन्होंने सभी जिला पंचायत भवनों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए जिन जिला पंचायतों में सौर ऊर्जा स्थापनाएं नहीं है वहां स्थापना करवाने तथा इसके मेंटेनेंस के लिए एनआरएलएम की दीदियों को प्रशिक्षित कर कार्य प्रदान करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, सचिव भीम सिंह, सचिव धर्मेश साहू, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा, संचालक एनआरएलएम अश्वनी देवांगन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

खास खबर

उरला की थ्रीडी फैक्ट्री हादसे पर कांग्रेस का हमला : दीपक बैज, "यह उद्योग प्रबंधन के साथ सरकार की भी आपराधिक लापरवाही"

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मृतकों के परिजनों को 1 करोड़, घायलों को 50 लाख मुआवजे की मांग

उरला स्थित थ्रीडी फैक्ट्री में ब्लास्ट से 3 मजदूरों की मौत और कई के घायल होने की घटना पर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेर लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे "उद्योग प्रबंधन के साथ सरकार की आपराधिक लापरवाही" करार देते हुए मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ और घायलों को 50-50 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है। **"ढाई साल में 300 से अधिक मजदूरों की मौत" :** दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के कुशासन में औद्योगिक हादसों में मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। ढाई साल में प्रदेश की औद्योगिक दुर्घटनाओं में 300 से अधिक मजदूरों की जान जा चुकी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ महीने पहले सक्ती के वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटने से 24 मजदूरों की मौत और 50 से अधिक घायल हुए थे। इसी तरह गोदावरी प्लांट रायपुर में भट्ठी विस्फोट और स्वदेश मेटालिक प्लांट बलौदाबाजार में 30 फीट से गिरकर श्रमिक की मौत हुई। ये सभी घटनाएं सुरक्षा के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाती हैं। **"सुरक्षा भगवान भरोसे" :** बैज ने आरोप लगाया कि उद्योगों में मजदूरों से जोखिम भरे काम करवाए जा रहे हैं। सुरक्षा उपकरणों का अभाव, बिना परमिट के काम सामान्य बात हो गई है। रायगढ़, सिलतरा और बलौदाबाजार जैसे क्षेत्रों में हुए हादसों में SOP का पालन न करना मुख्य कारण पाया गया है। उन्होंने कहा, "भाजपा सरकार की कॉरपोरेट परस्त नीतियों के कारण कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ कारखाना नियम 1962 का पालन नहीं हो रहा। शिकायतों के बावजूद सख्ती नहीं होने से हादसे लगातार हो रहे हैं। प्रशासन और श्रम विभाग जिम्मेदारी से बच रहे हैं।" **न्यायिक जांच और सुरक्षा ऑडिट की मांग :** कांग्रेस अध्यक्ष ने घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था और पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की। साथ ही प्रदेश के सभी उद्योगों का सुरक्षा ऑडिट कराकर तय मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की बात कही। बैज ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों की अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, लेकिन सरकार "शुतुरमुर्ग की तरह" आंख बंद किए बैठी है।

"नक्सल समाप्ति के दावे को 100 दिन, बस्तर के लिए कार्ययोजना कहां?"

दीपक बैज का सरकार पर हमला : नक्सल मुक्त पंचायतों को 1 करोड़ क्यों नहीं दिया?, बस्तर विकास के नाम पर सिर्फ बयानबाजी - कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य को "नक्सल मुक्त" करने के दावे को 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन बस्तर के विकास के लिए सरकार की कोई ठोस कार्ययोजना सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बस्तर के विकास के लिए विशेष ब्लूप्रिंट बनाने का वादा किया था। मुख्यमंत्री कई बार दिल्ली जाकर "ब्लूप्रिंट तैयार है" का बयान दे चुके हैं, लेकिन आज तक वह सामने नहीं आया।

"नक्सल मुक्त पंचायतों को 1 करोड़ दो" : बैज ने कहा कि सरकार ने खुद घोषणा की थी कि जो गांव नक्सल मुक्त होगा उसे 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अब मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक कह रहे हैं कि बस्तर सहित पूरा प्रदेश नक्सल मुक्त हो गया है। तो फिर सरकार अपनी घोषणा के अनुसार बस्तर संभाग के सभी गांवों के लिए तुरंत 1 करोड़ की राशि जारी क्यों नहीं कर रही? **कांग्रेस ने रखी थी शांति की नींव :** उन्होंने कहा कि बस्तर में शांति बहाली की ठोस नींव 2018 से 2023 के बीच कांग्रेस सरकार के समय "विश्वास, विकास, सुरक्षा" के मूलमंत्र के साथ रखी गई थी। बीजेपी यह न भूले कि 2003 में रमन सरकार आने से पहले नक्सलवाद सिर्फ बस्तर के 3 ब्लॉक में था, बीजेपी के राज में ही यह 14 जिलों तक फैला। **बस्तर के लिए 5 मांगें :** दीपक बैज ने सरकार से बस्तर के विकास के लिए ये मांगें कीं है कि :-

विशेष आर्थिक पैकेज - बस्तर को मुख्यधारा में लाने तत्काल विशेष पैकेज घोषित हो। रोजगार - बस्तर के युवाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान और वनोपज आधारित उद्योगों की योजना। NMDC मुख्यालय बस्तर में - NMDC का मुख्यालय हैदराबाद से हटाकर बस्तर में खोला जाए ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। खनिज संपदा की रक्षा -

---

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने नक्सल प्रभावित जिलों में विकास और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने निर्देश

नक्सल प्रकरण वापसी के लिए हर सप्ताह होगी बैठक, शासकीय वकीलों की बनेगी टीम

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास एवं विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नक्सल मामलों में जेल में निरुद्ध ऐसे आरोपियों, जिनके विरुद्ध गंभीर जनहानि के प्रकरण नहीं हैं, उनके मामलों की विधिसम्मत समीक्षा कर रिहाई की प्रक्रिया में आवश्यक कार्रवाई की जाए, जिसके लिए विधि विभाग की सहायता से अभियोजन एवं वकीलों का दल बनाकर प्रकरण वापसी पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक सप्ताह इसकी प्रगति की समीक्षा बैठक संबंधित प्रकरण से जुड़े जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे नक्सल प्रकरण जिनमें जनहानि नहीं हुई है उनमें जेल में निरुद्ध नक्सल आरोपियों की रिहाई आवश्यक है।

अति नक्सल प्रभावित रहे ग्रामों को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए

कभी अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के तीव्र विकास के लिए शासन द्वारा नक्सल मुक्त प्रस्ताव पारित कर ऐसे ग्रामों में 1-1 करोड़ रुपयों के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को आजीविका प्राप्त होने के साथ ग्रामों का विकास भी होगा। इसके लिए वर्तमान में 50 ग्रामों को चिन्हित किया गया है। जिसमें सुकमा के 20, बीजापुर के 20 एवं नारायणपुर के 10 ग्राम शामिल हैं।

15 अगस्त तक सभी नक्सल मुक्त हुए गांवों में तिरंगा यात्रा

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि आगामी 15 अगस्त 2026 को सभी नक्सल मुक्त हुए गांवों में तिरंगा फहराया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय एकता, विश्वास और जनभागीदारी का संदेश गांव-गांव तक पहुंचेगा।

पीड़ित और पुनर्वासित परिवारों को मिले आवास योजना का लाभ

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी नक्सल पीड़ित एवं पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के विशेष प्रावधानों के तहत आवास उपलब्ध कराया जाए। जिन क्षेत्रों में बड़ी नक्सली घटनाएं हुई हैं, वहां सामुदायिक स्मारकों का निर्माण भी कराया जाए ताकि शहीदों एवं पीड़ितों की स्मृतियों को सम्मान मिल सके। उन्होंने जिलावार नक्सली घटनाओं में शहीद हुए जवानों एवं मृत नागरिकों के मामलों, उनके परिजनों को प्रदान की गई सहायता तथा लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिजनों को शासन की सभी निर्धारित सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं और किसी भी स्तर पर विलंब न हो।

पुनर्वासितों पर घोषित प्रोत्साहन राशि का एक माह में होगा भुगतान

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पुनर्वास नीति का पालन करते हुए पुनर्वासित युवाओं को घोषित प्रोत्साहन राशि का अगले एक माह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही नक्सल पीड़ितों एवं पुनर्वासितों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए तैयार डेश बोर्ड में जानकारी प्रविष्ट करने को कहा। उन्होंने माओवादियों द्वारा लुटे गए हथियारों की बरामदगी पर अंतर्राज्यीय समिति बनाकर मिलान करने एवं जंगल में कोई भी हथियार ना छूटे यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख सचिव सुश्री निहारिका सिंह बारिक, सचिव श्रीमती नेहा चम्पावत, एडीजी विवेकानंद सिन्हा सहित गृह विभाग, पुलिस विभाग तथा संबंधित जिलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

"अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी : आस्था के नाम पर लूट" - कांग्रेस का बीजेपी-आरएस पर हमला

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण के नाम पर जुटाए गए चंदे और चढ़ावे में कथित घोटाले को लेकर बीजेपी-आरएस पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में उहउ सदस्य और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि "भगवान राम के नाम पर जुटाया गया चंदा भी बीजेपी-आरएस की राजनीतिक लूट का शिकार हो गया।" पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद थे।

कमलेश्वर के 3 बड़े सवाल

पटेल ने कहा कि देश के गरीब, किसान, मजदूर ने अपनी मेहनत की कमाई राम मंदिर के लिए दी। अब करोड़ों रामभक्त पूछ रहे हैं कि वह पैसा कहां गया?

उन्होंने 3 सवाल उठाए : जब ट्रस्ट का गठन PM की देखरेख में हुआ तो जवाबदेही कौन लेगा?, अगर सब ठीक था तो चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा क्यों दिया?, अगर कुछ गलत नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच से डर क्यों?

गंभीर आरोप : टेल ने कहा कि ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार किए जा चुके हैं। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने खुद बयान दिए हैं। आरएस के पूर्वी यूपी प्रभारी कृष्णमोहन को नया महासचिव बनाया गया है जिन पर लीपापोती के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 2024 की प्राण-प्रतिष्ठा पर 113 करोड़ और 25 नवंबर 2025 के ध्वजारोहण पर 10.12 करोड़ खर्च हुए। फर्जी रसीदों, नकद चढ़ावे और हेराफेरी के आरोप लगे हैं। लेकिन कार्रवाई सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर हो रही है, शीर्ष पदाधिकारियों को बचाया जा रहा है।

कांग्रेस की पांच मांगे : पीएम मोदी जवाब दें - ट्रस्ट गठन और निगरानी में PMO की क्या भूमिका रही? **तत्काल गिरफ्तारी** - चंपत राय, अनिल मिश्रा सहित सभी दोषियों पर FIR और गिरफ्तारी। **सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच** - स्वतंत्र न्यायिक जांच कराई जाए। **ट्रस्ट भंग हो** - नया पारदर्शी ट्रस्ट बनाया जाए। **फॉरेंसिक ऑडिट** - चंदे, चढ़ावे और खर्चों का पूरा ऑडिट सार्वजनिक हो।

दीपक : "भाजपा राम द्रोही"

प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, "भाजपा राम द्रोही है। पहले चंदे में हेराफेरी करवाई, अब चढ़ावे में चोरी।" उन्होंने आरोप लगाया कि रामशिला पूजन के नाम पर जुटे 14 हजार करोड़ का हिसाब आज तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट गठन गृहमंत्री अमित शाह ने किया था, इसलिए घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी पीएम मोदी और शाह की बनती है। बैज ने कहा, "भाजपा ने देवद्रव्य चोरी करने के महाप का संरक्षण किया है।" पत्रकार वार्ता में मलकीत सिंह गैदू, सुशील आनंद शुक्ला, विकास उपाध्याय, शैलेश नितिन त्रिवेदी सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद थे।

आर्थिक स्वावलंबन की नई पहचान बन रही है महतारी वंदन योजना : मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री ने जारी की महतारी वंदन योजना की 29वीं किश्त, 66 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में डीबीटी से 626 .25 करोड़ रुपये अंतरित

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से महतारी वंदन योजना की 29वीं किश्त जारी करते हुए प्रदेश की 66 लाख से अधिक माताओं-बहनों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 626.25 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की माताओं-बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वावलंबन की नई पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज की किश्त के साथ योजना के अंतर्गत अब तक 29 किश्तों में कुल 18,805.83 करोड़ रुपये की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में नारी शक्ति के सशक्तिकरण का जो व्यापक अभियान चल रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार उसी संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतार रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रवास के दौरान माताएं और बहनें स्वयं उन्हें बताती हैं कि महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है।

अनेक महिलाओं ने इस राशि से छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं, कई ने सिलाई-कढ़ाई एवं स्वरोजगार अपनाया है, जबकि बड़ी संख्या में परिवारों ने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में इसका उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के ये अनुभव इस योजना की वास्तविक सफलता और उसके दूरगामी सामाजिक प्रभाव के प्रमाण हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महतारी वंदन योजना के साथ-साथ श्लखपति दीदीश जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी महिलाओं की आय बढ़ाने, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर शत-प्रतिशत पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से बस्तर संभाग में इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए।

उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से प्रदेश में लागू की गई है। योजना के तहत 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक संबल मिलने के साथ परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण एवं एनीमिया की रोकथाम तथा स्वरोजगार जैसी गतिविधियों को भी नई मजबूती मिली है।

उप मुख्यमंत्री साव ने ई-मालखाना का किया शुभारंभ, नवीन बस व 4 वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

प्रदेश का पहला क्यूआर कोड आधारित डिजिटल ट्रैकिंग मालखाना प्रबंधन,

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

उप मुख्यमंत्री तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने कांकेर सिटी कोतवाली थाने में ई-मालखाना का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर जिला पुलिस को प्राप्त एक नवीन बस सहित चार वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। कांकेर सिटी कोतवाली में स्थापित ई-मालखाना क्यूआर कोड आधारित प्रदेश का पहला थाना है, जहां डिजिटल ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली को पारदर्शी, आधुनिकीकरण और सुव्यवस्थित ढंग से सरलीकृत किया गया है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने ई-मालखाना के शुभारंभ के बाद जब्तशुदा सामानों की ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने जिला पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए इसे बेहतर व्यवस्था बताया।

उप मुख्यमंत्री को पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि ई-मालखाना प्रणाली एक आधुनिक डिजिटल प्रबंधन व्यवस्था है, जिसके माध्यम से अपराध के दौरान विभिन्न प्रकरणों में जब्त की गई संपत्तियों एवं दस्तावेजों का सुरक्षित, पारदर्शी एवं व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस प्रणाली का उद्देश्य जब्त संपत्ति के रखरखाव को अधिक सुरक्षित, सुगम एवं जवाबदेह बनाना है, ताकि विवेचना एवं न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सामग्री को शीघ्रता से खोजकर प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि ई-मालखाना में जब्त किए गए वाहन, मोबाइल फोन, नकदी, हथियार, आभूषण, एनडीपीएस प्रकरणों से संबंधित सामग्री तथा अन्य केस प्रॉपर्टी का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जिससे प्रत्येक वस्तु का सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित डेटा उपलब्ध रहता है।

उल्लेखनीय है कि जिला पुलिस कांकेर द्वारा अपराध के दौरान जब्तशुदा हथियारों, उपकरणों व सामानों के रखरखाव की प्रबंधन प्रणाली को पारदर्शी, आधुनिकीकृत और सुव्यवस्थित बनाने के लिए ई-मालखाना शुरू किया गया है, जिसमें संपूर्ण रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जा रहा है। प्रत्येक बॉक्स के लिए क्यूआर कोड जनरेट किया गया है। बॉक्स में चस्पा क्यूआर कोड को स्कैन करते ही अपराध प्रकरण का विवरण, बॉक्स में बंद जब्त सामान की जानकारी संख्या और तिथि सहित मिल जाती है।

साथ ही जब्त सामान या उपकरण जैसे मोबाइल, नकदी, हथियार, आभूषण, मादक द्रव्य, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आदि का डिजिटल रिकॉर्ड क्यूआर कोड की स्कैनिंग से आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इससे डिजिटल अभिलेख और पेपरलेस वर्क भी आसान तरीके से मुहैया हो जाएगा। प्रदेश में क्यूआर कोड के जरिए मालखाने के डिजिटाइजेशन का कार्य कांकेर पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया है। प्रदेश के थानों में अब तक बार कोड स्कैनर की सुविधा थी, लेकिन क्यूआर कोड से डिजिटल मालखाना प्रबंधन प्रणाली पहली बार लागू की गई है।

श्री साव ने कार्यक्रम में उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिस जवानों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। सांसद भोजराज नाग, विधायक आशाराम नेताम, छग हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती किरण नरेटी तथा कांकेर नगर पालिका के अध्यक्ष अरुण कौशिक, उपाध्यक्ष उत्तम यादव, सतीश लाटिया, महेश जैन, आलोक ठाकुर, पूर्व विधायक श्रीमती सुमित्रा मारकोले, एएसपी आकाश श्रीश्रीमाल और जिला पंचायत के सीईओ हरेश मंडावी सहित गृह विभाग के अधिकारी और गणमान्य नागरिक भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

संपादकीय

विश्वास बहाली जरूरी

पारदशिर्ता हेतु कठोर फैसले लेने से न चूके ट्रस्ट

देश के करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था-विश्वास को आहत करने वाला चंदा-चोरी प्रकरण सामने आने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक में आखिरकार महामंत्री चंपत राय व सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। अब ट्रस्ट के अन्य सदस्य कृष्ण मोहन को अंतरिम महामंत्री बनाया गया है। राममंदिर के चंदे में हेरफेर से उठे देशव्यापी विवाद के बाद प्राथमिकी दर्ज होने, एसआईटी के गठन और कुछ गिरफ्तारियों के बाद ये इस्तीफे अपरिहार्य थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ दो इस्तीफों से श्रद्धालुओं के भरोसे की बहाली हो पाएगी? जैसा कि नवनियुक्त अंतरिम महामंत्री कृष्ण मोहन ने कहा कि मेरी प्राथमिकता है कि चंदा चोरी के मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा,उसे कड़ी सजा मिले।

उन्होंने स्वीकारा कि ट्रस्ट प्रबंधन और संचालन में कहीं न कहीं खामियां रही हैं। उन्हें दूर करने का प्रयास होगा। साथ ही माना कि जो तथ्य सामने आए हैं उससे न्यास की छवि धूमिल हुई है। एक अविश्वास का भाव उत्पन्न हुआ। ट्रस्ट की प्रतिष्ठा को फिर स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कृष्ण मोहन भारतीय वन सेवा में शामिल होने से पहले कुछ सालों तक परमाणु ऊर्जा विभाग में परमाणु वैज्ञानिक भी रहे हैं। वे दलित समुदाय से आते हैं। वे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारी रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज ने सोमवार को अयोध्या में उन बहुमूल्य वस्तुओं को मीडिया के सामने प्रदर्शित किया, जिनके गायब होने को लेकर अटकलें लगायी जा रही थीं।

बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के संचालन के लिये विशिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिये एक समिति का गठन किया गया है। इसी क्रम में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगली बैठक बाईस जुलाई को होगी। जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिये जाने का अनुमान है। कहा जा रहा है कि तब तक चंदा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी।

लेकिन सवाल यह है कि आस्था व विश्वास से खिलवाड़ के कृत्य की जांच के लिये क्या एसआईटी की जांच पर्याप्त है? क्या चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे मात्र से उनकी लापरवाही और गैर जिम्मेदार व्यवहार पर कारर्वाई पूरी मान ली जाए? क्या इतनी कारर्वाई मात्र से सारे प्रकरण से संदेह के बादल छंट जाएंगे और लोगों का खंडित भरोसा फिर से कायम हो जाएगा? अब तो संघ प्रमुख ने भी स्वीकारा है कि इस घटनाक्रम से व्यापक हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।

ऐसे में अब ट्रस्ट को कठोर फैसले लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखानी चाहिए। निस्संदेह, समय रहते यदि ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने चंदा प्रकरण में संवेदनशीलता के साथ कड़ी निगाह रखी होती तो यह बड़ा विवाद न खड़ा होता। शुरुआती दौर में जब मामले की सुगबुगाहट सामने आई तो तभी ट्रस्ट के पदाधिकारियों को सख्त कारर्वाई करनी चाहिए थी। ऐसे में ट्रस्ट के पदाधिकारियों की कायर्शैली पर सवाल उठने स्वाभाविक ही हैं। कुछ लोग तो ट्रस्ट को भंग करके नये सिरे से इसके गठन की बात कहते रहे हैं। बहरहाल, इतना तय है कि ट्रस्ट की कारगुजारियों में सबकुछ न तो पारदर्शी था और न ही सब कुछ नियम अनुसार ही चला।

कहा जा रहा है कि कुछ पदाधिकारियों के पास जरूरत से ज्यादा अधिकार थे, जिसके चलते अन्य सदस्य उदासीन बने रहे। यही वजह है कि कुछ लोग एसआईटी से इतर एक उच्च स्तरीय जांच की मांग इस मामले में करते रहे हैं। निस्संदेह, बहुचर्चित चढ़ावा चोरी प्रकरण की गूंज पूरी दुनिया में हुई है, जिसने संघ,भाजपा, केंद्र सरकार व प्रदेश की सरकार को असहज स्थिति में ला खड़ा किया है। यही वजह है कि लोग इस मामले में किसी लीपा-पोती के बजाय भक्तों के दान की पारदर्शी व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। जिससे गाहे-बगाहे देश के अन्य प्रमुख तीर्थस्थलों में भी उठने वाले चंदे में हेरा-फेरी के मामलों का हमेशा के लिये पटाक्षेप हो सके। साथ ही श्रद्धालुओं को यह भी पता लग सके कि दान की राशि का उपयोग कैसे किया जा रहा है।

यूपी वक़्फ बोर्ड में हिन्दुओं की एंट्री ऐतिहासिक न्याय

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा वक़्फ बोर्ड में दो हिंदू (गैर-मुस्लिम) सदस्यों की नियुक्ति के फैसले ने देश की सियासत और सामाजिक विमर्श में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर लिए गए इस फैसले को जहां एक पक्ष ह्यऐतिहासिक न्यायह्न, पारदशिर्ता और बहुसंख्यक समाज के हितों की रक्षा के रूप में देख रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे धार्मिक स्वायत्तता में दखल और मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रहा है। वैसे, नए वक़्फ बोर्ड में हिंदू ही नहीं, महिलाओं और पसमांदा समाज के मुसलमानों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह मुद्दा केवल एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि इसके तार जमीनी विवादों, ऐतिहासिक दावों, वक़्फ कानून की असीमित शक्तियों और भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे से जुड़े हुए हैं। योगी सरकार और हिंदू विचारकों का मानना है कि यह फैसला किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि एकतरफा फैसलों पर रोक लगाने और वक़्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में ह्यचेक एंड बैलेंसह्न (संतुलन) स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं :

क़ानून का एक बुनियादी सिद्धांत है कि किसी भी विवाद में दोनों पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। अब तक स्थिति यह थी कि यदि वक़्फ बोर्ड किसी हिंदू की जमीन या किसी प्राचीन मंदिर पर अपना दावा ठोकता था, तो उस विवाद का निपटारा करने वाली कमेटी में सभी सदस्य मुस्लिम होते थे। ऐसे में पीड़ित पक्ष (हिंदू) को हमेशा यह मलाल रहता था कि बोर्ड के भीतर उसका पक्ष रखने या समझने वाला कोई नहीं है। दो हिंदू सदस्यों की मौजूदगी से बोर्ड के भीतर एक बहु-सांस्कृतिक और निष्पक्ष दृष्टिकोण विकसित होगा। वक़्फ एक्ट, 1995 (विशेषकर 2013 के संशोधनों के बाद) के तहत बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक़्फ की संपत्ति घोषित करने के बेहद व्यापक अधिकार मिले हुए हैं। यदि बोर्ड किसी जमीन को अपनी संपत्ति मान लेता है, तो पीड़ित व्यक्ति सीधे दीवानी अदालत नहीं जा सकता; उसे वक़्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील करनी होती है। हिंदू पक्ष का तर्क है कि जब बोर्ड के पास इतनी असीमित शक्तियां हैं, तो उसका स्वरूप पूरी तरह एकतरफा नहीं होना चाहिए, खासकर तब, जब विवाद गैर-मुस्लिमों की संपत्तियों से जुड़ा हो।

इस पर योगी सरकार और समर्थकों का आरोप है कि दशकों से राजनीतिक दलों ने वक़्फ बोर्ड को एक स्वायत्त साम्राज्य की तरह काम करने की छूट दे रखी थी, ताकि मुस्लिम वोट बैंक को साधा जा सके। इस व्यवस्था में सुधार करना तुष्टिकरण को खत्म कर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को धरातल पर उतारना है। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विरोध कर रहे मौलानाओं का तर्क है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। वक़्फ मूल रूप से इस्लाम के अल्लाह की राह में दान के सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था है। उनका कहना है कि जिस तरह तिरुपति देवस्थानम, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या अन्य हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में किसी गैर-हिंदू को सदस्य नहीं बनाया जा सकता, उसी तरह वक़्फ बोर्ड में हिंदुओं की नियुक्ति करना इस्लामी कानूनों और परंपराओं के खिलाफ है।

विपक्षी दलों (जैसे सपा, कांग्रेस और ओवैसी की एआईएमआईएम) का आरोप है कि सरकार वक़्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करने या उसकी शक्तियों को कमजोर करने के लिए यह कदम उठा रही है। मुस्लिम बुद्धिजीवियों का एक वर्ग इसे समुदाय के भीतर असुरक्षा की भावना पैदा करने और बहुसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति का हिस्सा मानता है। उनका कहना है कि यदि बोर्ड में कोई विसंगति थी, तो उसे कानूनी सुधारों या मुस्लिम समाज के ही ईमानदार विशेषज्ञों को शामिल करके सुधारा जा सकता था। इस प्रशासनिक बदलाव की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, इसे समझने के लिए उन विवादों पर नजर डालना जरूरी है, जहां वक़्फ बोर्ड के दावों के कारण गैर-मुस्लिमों को ऐसा लगा कि उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। कुछ समय पहले तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के थिरुचेंथुरई गांव में एक बड़ा विवाद सामने आया था। वहां एक हिंदू व्यक्ति जब अपनी कृषि भूमि बेचने गया, तो उसे पता चला कि पूरे गांव की जमीन (जिसमें 1500 साल पुराना सुंदरेश्वरर मंदिर भी शामिल है) वक़्फ बोर्ड की है। ग्रामीणों का तर्क था कि उनके पास सदियों पुराने दस्तावेज हैं, लेकिन वक़्फ के एकतरफा दावे के कारण वे अपनी ही जमीन बेचने या ट्रांसफर करने में लाचार हो गए। ऐसे मामलों ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में एक डर और असंतोष का माहौल पैदा किया।

इसी तरह उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में ऐसी शिकायतें आम रही हैं, जहां प्राचीन टीलों, सार्वजनिक पार्कों या ग्राम समाज की जमीनों पर रातों-रात मजारें खड़ी हो गईं और बाद में उन्हें वक़्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करा लिया गया। जब स्थानीय हिंदू आबादी या पंचायत ने इस पर आपत्ति जताई, तो बोर्ड के स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं हुई। प्रशासनिक अधिकारियों को भी वक़्फ एक्ट की पेचीदगियों के कारण कारर्वाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ताजमहल से लेकर कई राष्ट्रीय स्मारकों और ऐतिहासिक धरोहरों (जो मूल रूप से प्राचीन हिंदू स्थापत्य काल से जुड़ी मानी जाती हैं या एएसआई के अधीन हैं) पर भी समय-समय पर वक़्फ बोर्ड द्वारा मालिकाना हक़ या नमाज पढ़ने के अधिकार के दावे किए जाते रहे हैं। इन विवादों में मध्यस्थता या निष्पक्ष समीक्षा के लिए बोर्ड के भीतर किसी भी गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व का न होना हमेशा खटकता रहा है।

कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम प्रशासनिक सुधार और सामाजिक संतुलन की दृष्टि से एक बड़ा प्रयोग है। बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों के आने से कम से कम उन मामलों में पारदशिर्ता आएगी, जहां हिंदू संपत्तियों या विवादित स्थलों का मामला फंसा हुआ है। यह बोर्ड को अधिक जवाबदेह बनाएगा और एकतरफा फैसलों के आरोपों से बचाएगा। उधर सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती मुस्लिम समुदाय के भीतर फैले अविश्वास को दूर करना होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन सदस्यों की भूमिका वक़्फ के धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों में दखल देने की न होकर केवल प्रशासनिक, वित्तीय पारदर्शिता और भूमि विवादों के निष्पक्ष निपटारे तक सीमित रहे। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में संस्थाओं का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, जो समाज के सभी वर्गों में विश्वास पैदा कर सके। यदि यह निर्णय केवल राजनीति से ऊपर उठकर जमीनी विवादों को सौहादर्पूर्ण ढंग से सुलझाने का जरिया बनता है, तो इसे भविष्य में एक सकारात्मक सुधार के रूप में याद किया जाएगा। वैसे कुछ लोग वक़्फ बोर्ड की तुलना राम मंदिर ट्रस्ट से भी कर रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि वक़्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है, या फिर वे जानबूझकर विवाद खड़ा कर रहे हैं।

इज्जत बलात्कारी की जाती है बलात्कार पीड़िता की नहीं

राजीव चौबे
(फाउंडर राष्ट्रीय चेतना न्यूज)

भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रचलित एक जुमला मुझे कई वर्षो से खटक रहा है

एक शब्द है 'लूट' लूट याने की बलपूर्वक किसी की संपत्ति को हथियाना ये मान लीजिये छगन ने जगन की मोटर साइकिल लूट ली इस स्थिति मोटरसाइकिल अब छगन की हो गई, इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं छगन और जगन के पास आठ आठ छतरियां हैं छगन ने जगन से दो छतरियां लूट ली अब जगन के पास छह छतरियां रह गई याने की जगन की छतरियां कम हो गई वहीं छगन के पास दस छतरियां हो गई याने की छगन की छतरियां बढ़ गई। अर्थात जिस किसी भी वस्तु की लूट होती है लुटने वाले के पास वो कम हो जाती है और लूटने वाले के पास वो बढ़ जाती है।

अब शब्द कोष के कुछ और शब्द हैं, इज्जत, आबरू और अस्मत इज़्जत का अर्थ 'सम्मान', 'प्रतिष्ठा', 'गरिमा' और 'मर्यादा' होता है? यह शब्द उत्तर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की संस्कृतियों में बहुत महत्व रखता है? यह किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और दूसरों की नजरों में उसके आदर को दर्शाता है? इसके मुख्य पहलू हैं सम्मान, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, और सामाजिक स्वीकृती, यह शब्द मूल रूप से अरबी भाषा के शब्द 'izzat से आया है, जिसे फारसी में भी अपनाया गया था और बाद में यह उर्दू का हिस्सा बन गया, इज्जत, आबरू और अस्मत शब्दों के अर्थ तो हम जान गए अब समझते है कोई मनुष्य इज्जत आबरू कैसे प्राप्त करता है, दरअसल मानव समाज में मान सम्मान इज़्जत शब्द भाववाचक संज्ञा है और मनुष्य अपने सद्कर्मों से समाज में इज्जत प्राप्त करता है इसका मतलब सज्जन की इज्जत होती है और दुर्जन की इज्जत नहीं होती। ये तो हो गया इज्जत कमाने का तरीका अब इज्जत गंवाने या लुटाने की बात करें तो ये तय है कि सद्कर्मों से यदि इज्जत कमाई जाती है तो दुष्कर्मों से इज्जत गंवई जाती होगी अर्थात बुरे कर्मो से समाज में मनुष्य की इज्जत घटती है, खोती है, या लुटती है।

अब बोलचाल की भाषा में इज्जत और लूटने जैसे शब्दों के प्रयोग पर गौर करें

'इज्जत लुटना' इस शब्द युग्म का प्रयोग हमारे बोलचाल की भाषा में कैसे होता है? हमारे देश में जब भी किसी स्त्री के साथ अनाचार की घटना होती है तब सहज रूप से कहा जाता है कि फलां महिला की इज्जत लुट गई, या आबरू लुट गई, या फिर अस्मत लुट गई! सामूहिक बलात्कार की घटना में चार लोगों ने मिलकर एक मासूम की इज्जत लूट ली! दरिंदे ने डरा धमका कर बेबस की इज्जत लूट ली! मनचलों ने खेत में काम करने गई महिला की इज्जत लूट ली!

अखबारों की सुर्खियां होती हैं - फलां ने फलां की इज्जत लूट ली, फिल्मों के संवाद होते हैं, बलात्कारी ने एक मासूम की इज्जत लूट ली! तब यह प्रश्न दशकों से मेरे मन को कचोटता है की बलात्कार की घटना में एक दरिंदे द्वारा पीड़िता की इज्जत लूटना शब्द के प्रयोग का सीधा सीधा अर्थ होता है पीड़िता की इज्जत का घटना तो क्या हमर समाज ये मानता है कि जिस स्त्री के साथ बलपूर्वक अनाचार किया गया हो उसकी इज्जत कम हो जाती है? इस स्थिति में जिसने इज्जत लूटी क्या उसकी इज्जत और बढ़ गई?

पिछले कई सालों से इस देश के बड़े बड़े भाषा विद, समाज शास्त्री, विधि विशेषज्ञ, सोशल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ है उसकी इज्जत कैसे लुट गई? एक तो पीड़िता अपने साथ हुए भयानक शारीरिक और उससे कहीं अधिक मानसिक प्रतड़ना को झेले और फिर समाज कहे कि उसकी इज्जत लूट गई! क्या कभी किसी को ये नहीं लगा कि दुष्कर्म के मामले में इज्जत तो पीड़िता की नहीं बल्कि दुष्कर्मी की लुटती है? बावजूद इसके दुष्कर्म की घटना पर हम बड़ी सहजता से कह देते हैं कि फलां की इज्जत लुट गई! समाज में बड़ी सहज मान्यता बन गई है बड़ी सहजता से कह देते हैं लड़कों का क्या है? आखिर इज्जत तो लड़की की गई न! इसके मायने क्या हैं? जिसने जघन्य अपराध किया उसका कुछ नहीं गया और जिस बेचारी के साथ दुष्कृत्य हुआ उसकी इज्जत चली गई!

आप मैं और ये पूरा समाज किस आधार पर तय करता है कि बलात्कार पीड़िता की इज़्जत चली गई। कई घटनाओं में बलात्कार के बाद पीड़िता की हत्या कर दी जाती है तब भी समाज बड़ी सहजता से कह देता है जान भी गई और इज़्जत भी इसका मतलब पीड़िता अपनी जान देकर भी अपनी इज़्जत नहीं बचा पाई?

जैसा की मैंने पहले बताया शब्द मूल रूप से अरबी भाषा के शब्द 'izzat से आया है, जिसे फारसी में भी अपनाया गया था और बाद में यह उर्दू का हिस्सा बन गया, दरअसल भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में बोलचाल की भाषा में हिंदी और उर्दू का जबरदस्त मिश्रण है उर्दू के ज्यादातर शब्द फारसी से लिए गए हैं वहीँ हिंदी के ज्यादार शब्द संस्कृत से आते हैं अब यहाँ समझने वाली बात ये है की हर भाषा में उस संस्कृति की गंध होती है जहाँ उस भाषा का जन्म होता है जैसे की परिष्कृत हिंदी पाली और संस्कृत अदि भाषाओँ में आप को भारतीय संस्कृति की गंध मिलेगी वैसे ही उर्दू में आपको अरबी और फारसी संस्कृति की गंध मिलती है इसी लिए हिंदी में रेप के लिए, महिला का साथ, दुराचार, अनाचार, बलात्कार जैसे शब्दों का प्रयोग होता है क्यों कि भारतीय संस्कृति ये कभी स्वीकार नहीं करती कि बलात यौन शोषण से स्त्री का सम्मान घटता है! जबकि अरबी और फारसी संस्कृति के अनुसार रेप का मतलब खबातीन की इज्जत लुटना होता है। बावजूद इसके आज देश के पूरे हिंदी भाषी भूभाग में ब्लात्कार पर पीड़िता की इज्जत लुटना जैसे शब्द का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है।

आइये आप और हम समाज को जागृत करने का प्रयास करें और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर की पीड़िता की इज़्जत लुटने जिसे शब्द को भारतीय शब्दकोष से ही विलोपित करने का प्रयास करें।

विकसित भारत की राह में जनसंख्या संतुलन का प्रश्न

ललित गर्ग

प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम है- युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं को साकार करना-आज और भविष्य के लिए। यह विषय स्पष्ट संकेत देता है कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य केवल उसकी जनसंख्या के आकार से नहीं, बल्कि उस जनसंख्या की गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और अवसरों से निर्धारित होता है। भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह स्थिति एक ओर विशाल मानव संसाधन का अवसर प्रस्तुत करती है, तो दूसरी ओर संसाधनों, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और पर्यावरण पर अभूतपूर्व दबाव भी उत्पन्न करती है। इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस भारत के लिए केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि गंभीर आत्ममंथन का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक अवसरों पर छोटे परिवार के महत्व पर बल देते हुए कहा है कि जो परिवार स्वेच्छा से परिवार नियोजन अपनाते हैं, वे राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनका यह संदेश बताता है कि जनसंख्या संतुलन किसी एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे देश के सतत विकास का विषय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न पदाधिकारियों ने भी समय-समय पर यह कहा है कि जनसंख्या नीति सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए तथा इसका उद्देश्य किसी समुदाय को लक्ष्य बनाना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित, संसाधनों के संतुलित उपयोग और सामाजिक समरसता को सुनिश्चित करना होना चाहिए।

भारत आज वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र तभी पूरी तरह साकार हो सकता है, जब विकास की गति और जनसंख्या वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित हो। यदि जनसंख्या अनियंत्रित गति से बढ़ती रहे और संसाधनों का विस्तार उसी अनुपात में न हो, तो विकास की उपलब्धियां भी पर्याप्त सिद्ध नहीं होंगी। रोजगार के अवसर सीमित होंगे, कृषि योग्य भूमि सिकुड़ेगी, जल संकट गहराएगा, महानगरों पर दबाव बढ़ेगा और पर्यावरणीय असंतुलन गंभीर होता जाएगा। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या संबंधी विमर्श तथ्यों, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक सद्भाव पर आधारित हो। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देता है और जनसंख्या नीति का उद्देश्य भी समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू होने वाला, न्यायसंगत एवं पारदर्शी ढांचा होना चाहिए। परिवार नियोजन, महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, विवाह की उपयुक्त आयु, आर्थिक सशक्तिकरण तथा जन-जागरूकता ऐसे उपाय हैं, जिनसे बिना किसी भेदभाव के जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। विश्व के अनेक अनुभव बताते हैं कि जैसे-जैसे शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा और आर्थिक विकास बढ़ता है, वैसे-वैसे प्रजनन दर स्वाभाविक रूप से घटती है।

भारत के सामने एक अन्य गंभीर चुनौती अवैध घुसपैठ की भी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में यदि अवैध रूप से लोगों का प्रवेश होता है और वे बिना वैधानिक प्रक्रिया के देश में बस जाते हैं, तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, संसाधनों के वितरण तथा जनसांख्यिकीय संतुलन पर प्रभाव पड़ सकता है। यह विषय जनसंख्या नियंत्रण से अलग, कानून व्यवस्था और सीमा सुरक्षा का प्रश्न है। अतः सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना, अवैध प्रवासन पर प्रभावी नियंत्रण रखना तथा नागरिकता संबंधी कानूनों का निष्पक्ष पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह मुद्दा किसी धर्म या समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि कानून के शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। भारत को यह भी समझना होगा कि केवल कठोर कानून बना देना पर्याप्त नहीं होगा। चीन ने अपने समय में एक-संतान नीति अपनाई, लेकिन बाद में बदलती परिस्थितियों के कारण उसे वापस लेना पड़ा। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था चीन से भिन्न है। इसलिए भारत के लिए अधिक उपयुक्त मार्ग वह होगा जिसमें कानून के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता, स्वैच्छिक सहभागिता, शिक्षा और सकारात्मक प्रोत्साहन को प्राथमिकता दी जाए। छोटे परिवारों को प्रोत्साहन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है।

पिछले एक वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि विश्व की जनसंख्या लगभग 8.19 अरब से बढ़कर 8.30 अरब हो गई है, अर्थात एक वर्ष में लगभग 6.9 करोड़ लोगों की वृद्धि हुई है, जो लगभग 0.83 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाती है। दूसरी ओर भारत की जनसंख्या 1.45 अरब से बढ़कर लगभग 1.47 अरब हो गई है, यानी एक वर्ष में लगभग 1.25 करोड़ लोग और जुड़ गए। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 0.87-0.89 प्रतिशत के बीच है, जो वैश्विक औसत से थोड़ी अधिक है। भारत विश्व की कुल आबादी का लगभग 17.8 प्रतिशत हिस्सा रखता है। इतनी विशाल जनसंख्या के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, जल, ऊर्जा, कृषि भूमि और पर्यावरण पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। यदि जनसंख्या वृद्धि और विकास के बीच संतुलन स्थापित नहीं किया गया, तो विकसित भारत का लक्ष्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इसलिए केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है, बल्कि जनसंख्या स्थिरीकरण, मानव संसाधन विकास और संसाधनों के संतुलित नियोजन को भी समान प्राथमिकता देनी होगी।

भारत में जनसंख्या का प्रश्न केवल सामाजिक या आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक विमर्श का भी विषय बन गया है। जातिगत जनगणना और विभिन्न जाति-समुदायों की जनसंख्या को लेकर राजनीतिक दल अक्सर अपने-अपने वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति अपनाते दिखाई देते हैं। अनेक विश्लेषकों का मानना है कि यदि जनसंख्या के आंकड़ों का उपयोग केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण या चुनावी लाभ के लिए किया जाएगा, तो यह राष्ट्रीय एकता और समावेशी विकास की भावना के विपरीत होगा। इसके विपरीत, चीन ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप लंबे समय तक कठोर जनसंख्या नियंत्रण नीति अपनाकर जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया, यद्यपि बाद में बदलती जनसांख्यिकीय चुनौतियों के कारण उसने उस नीति में संशोधन भी किया। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था अलग है, इसलिए यहां समाधान कठोर दमनात्मक उपायों के बजाय समान रूप से लागू होने वाली जनसंख्या नीति, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, परिवार नियोजन, जन-जागरूकता और कानून के निष्पक्ष अनुपालन में निहित है। जनसंख्या के प्रश्न को जाति, धर्म या वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय विकास, सामाजिक संतुलन और भविष्य की पीढ़ियों के हित के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है।

विश्व जनसंख्या दिवस 2026 की थीम भी इसी दिशा में संकेत करती है कि यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और अवसर मिलेंगे, तो वे स्वयं जिम्मेदार नागरिक बनकर संतुलित परिवार और सतत विकास की दिशा में योगदान देंगे। भारत की लगभग आधी आबादी युवा है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश तभी राष्ट्र की शक्ति बनेगा, जब यह शिक्षित, कुशल, स्वस्थ और आत्मनिर्भर होगा। अन्यथा यही विशाल युवा आबादी बेरोजगारी, असंतोष और सामाजिक चुनौतियों का कारण भी बन सकती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में एक व्यापक, वैज्ञानिक और सर्वसम्मत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर गंभीर विचार किया जाए। ऐसी नीति में समानता, पारदशिर्ता, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय हित को सवीच्च प्राथमिकता मिले। इसके साथ ही जनसंख्या संबंधी किसी भी चर्चा में सामाजिक सौहार्द, तथ्यपरक विश्लेषण और जिम्मेदार सार्वजनिक विमर्श बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। किसी भी प्रकार की अतिरंजना या विभाजनकारी दृष्टिकोण समाधान नहीं, बल्कि नई समस्याओं को जन्म दे सकता है।

विश्व जनसंख्या दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि विकसित भारत का सपना केवल आर्थिक विकास से पूरा नहीं होगा। इसके लिए जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन, मानव पूंजी में निवेश, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं को अवसर, प्रभावी सीमा प्रबंधन और दीघर्कालिक राष्ट्रीय नीति-इन सभी का समन्वित प्रयास आवश्यक है। यदि भारत समय रहते जनसंख्या संतुलन, मानव विकास और संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग की दिशा में ठोस कदम उठाता है, तो वर्ष 2047 तक विकसित, समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का लक्ष्य अधिक यथार्थ रूप में साकार हो सकेगा। जनसंख्या केवल संख्या नहीं, बल्कि राष्ट्र की शक्ति है, बशर्ते वह शिक्षित, स्वस्थ, अनुशासित, उत्पादक और संतुलित हो। यही विश्व जनसंख्या दिवस का वास्तविक संदेश है।

कविता का कोना

नये लेख लिख जाय

यह जग खेती करम की,
बोना लूना होय
जैसा बोना होयगा, वही
काटना होय
परिश्रम करते जाइये, अपना
भाग्य बनाय
किस्मत उसके साथ है, जो
परिश्रम में जाय
पन्ने लौटें भूत के, देखे
जग इतिहास
जिनके जैसे करम है, पूरी
होती आस।
ज्ञानी रावण हारता, अहंकार
जब होय
सौ सौ कौरव हारते, जीत
पांडव होय।
कभी हार नहि मानिये, परिश्रम
करते जाय
एडीसन नहि हारता, बल्ब
रोशनी लाय।
दोष किसी को दें नहीं, अपनी
राह बनाय
सब करमो का खेल है, नये
लेख लिख जाय।
अर्जुन हिम्मत किया तो, समर
जीत वो लेय
निर्णय समुचित लीजिये, सदा
सफलता लेंय।
स्याही होती करम की, भाग्य
तभी लिख पाय
पर को गाली देन से, राहें
मिलती नाय।
फुटबालें बनना नहीं, बिजली
खंभा होय
तुफानो को झेलिये, कभी न
हिलना होय।

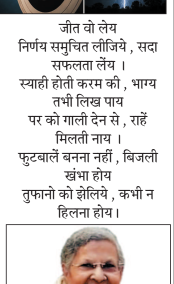

छत्तीसगढ़ रत्न
डॉ. शिरोमणि माथुर

"युवाओं की आशाओं को साकार करना" थीम पर पोस्टर-स्लोगन प्रदर्शनी का आयोजन

भिलाई इस्पात संयंत्र : जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र में विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस-2026 के अवसर पर प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग द्वारा ओपीडी परिसर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण, प्रजनन स्वास्थ्य, उत्तरदायी अभिभावकत्व और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस वर्ष की वैश्विक थीम "आज और भविष्य के लिए युवाओं की आशाओं एवं आकांक्षाओं को साकार करना" पर आधारित विभिन्न गतिविधियां की गईं।

पोस्टर-स्लोगन प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र : कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद पोस्टर एवं स्लोगन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी में पीजीकॉन, एपीकॉन, एसएसकॉन के विद्यार्थियों और नर्सिंग स्टाफ द्वारा तैयार 31 पोस्टर एवं 11 स्लोगन प्रदर्शित किए गए। इनके माध्यम से परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और संतुलित जनसंख्या वृद्धि जैसे विषयों पर प्रभावी संदेश दिए गए। कार्यक्रम में लगभग 70 प्रतिभागियों ने सहभागिता की।

स्वस्थ परिवार से ही सतत विकास संभव : मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा सेवाओं के प्रमुख डॉ. कौशलेंद्र ठाकुर ने कहा कि स्वस्थ परिवार और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं, जनजागरूकता और जिम्मेदार प्रजनन संबंधी निणर्यों को बढ़ावा देना आवश्यक है। चिकित्सा समुदाय और समाज के सामूहिक प्रयासों से ही जनसंख्या स्थिरीकरण का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. उदय कुमार ने आयोजन समिति और विद्यार्थियों की रचनात्मक भागीदारी की सराहना की। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभागाध्यक्ष डॉ. नीना गुहा ने कहा कि युवाओं को जागरूक और सशक्त बनाना स्वस्थ परिवार एवं समृद्ध समाज की आधारशिला है।

विजेताओं को किया गया पुरस्कृत : कार्यक्रम में पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मूल्यांकन दंत चिकित्सा विभागाध्यक्ष डॉ. अन्नपूर्णी, पैथोलॉजी विभाग की डॉ. निली कुजूर और श्वसन रोग विभागाध्यक्ष डॉ. सोनाली त्रिवेदी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. हिमानी गुप्ता ने दिया। इस अवसर पर उपस्थित सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों ने जनसंख्या स्थिरीकरण एवं परिवार नियोजन की जागरूकता को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

खास खबर

40 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए अंकालू राम साहू, सहकर्मियों ने दी भावभीनी विदाई

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

ग्राम भोथीपार खुर्द (नया) स्थित राजाराम मेझ प्रोडक्ट कंपनी के डेक्सट्रोज विभाग में 40 वर्षों तक अपनी सेवाएं देने वाले अंकालू राम साहू 60 वर्ष पूर्ण करने पर शुक्रवार को सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर कंपनी के सहकमिर्यो ने उन्हें भावभीनी विदाई दी।

40 साल तक निभाया दायित्व : अंकालू राम साहू वर्ष 1986 से 2026 तक कंपनी के डेक्सट्रोज विभाग में कार्यरत थे। अपनी मेहनत, ईमानदारी और मिलनसार व्यवहार के कारण वे सभी कर्मचारियों के बीच लोकप्रिय थे। सेवानिवृत्ति के अवसर पर सहकर्मियों ने उन्हें श्रीफल, प्रतीक चिन्ह और शाल भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य और दीर्घायु जीवन की कामना की।

सहकर्मियों ने किया याद : विदाई समारोह में बोलते हुए कमर्चारियों ने कहा कि अंकालू राम साहू ने चार दशकों तक पूरी निष्ठा से काम किया। उनका व्यवहार सभी के साथ मधुर रहा और वे हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहते थे। विदाई समारोह में योगेन्द्र दास वैष्णव, अध्यक्ष राष्ट्रीय ग्लुकोज स्टार्च केमिकल मजदूर संघ, टाइम कीपर मूलचंद साहू, इंचार्ज पीलू साहू, फोरमेन रूपेश साहू, फिटर पालक यादव, खेमलाल निषाद, तेनसिंह यादव, धनेश्वर साहू, हीरा साहू, हुकुम, भागवत वर्मा, युवराज पटेल, लीलाराम पटेल, विमल साहू, लोरी यादव, उत्तम साहू सहित कंपनी के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। समारोह के अंत में सभी ने एकजुट होकर सेवानिवृत्त कर्मचारी के स्वस्थ और सुखमय जीवन की कामना की।

कार से खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल, चलती कार की छत पर करतब, नियमों की उड़ाई धज्जियां

सूरजपुर। जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अजबनगर के मोरभंज में एक युवक द्वारा चलती कार से खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक न सिर्फ ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहा है, बल्कि अपनी और दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहा है।

वीडियो में क्या दिख रहा है : वायरल वीडियो में एक चलती कार की छत पर युवक खतरनाक करतब करते नजर आ रहा है। कार तेज गति से पर्यटन स्थल की सड़क पर दौड़ रही है और युवक स्टंटबाजी कर रहा है। इस दौरान आसपास अन्य वाहन और पर्यटक भी मौजूद थे। स्टंट के दौरान युवक ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी और न ही कोई सुरक्षा इंतजाम किया गया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लापरवाही से नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं।

सोशल मीडिया पर आक्रोश : वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग नाराजगी जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि पर्यटन स्थल जैसी जगह पर इस तरह की स्टंटबाजी से न सिर्फ स्टंट करने वाले की जान को खतरा है, बल्कि वहां मौजूद अन्य पर्यटकों और राहगीरों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है।

पुलिस जांच में जुटी : मामले के सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है और कार व चालक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पर्यटन स्थलों पर इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी युवक की तलाश में जुटी है।

रायपुर में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत QRT टीम को मिले 10 नए वाहन

पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने दिखाई हरी झंडी, हेल्पलाइन 94792 10632 पर करें कॉल

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

शहर में सुगम यातायात और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी को 10 नए आधुनिक वाहन उपलब्ध कराए हैं। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने शुक्रवार को इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

तुरंत पहुंचेगी क्यूआरटी टीम

पुलिस कमिश्नर ने रवाना करने से पहले शहर के जाम प्रभावित प्रमुख स्थानों की समीक्षा कर अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने सभी क्यूआरटी टीमों को निर्देश दिए कि ट्रैफिक बाधित होने की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर यातायात सामान्य करें, ताकि नागरिकों को असुविधा न हो। क्यूआरटी टीमों को आधुनिक उपकरणों और संसाधनों से सुसज्जित किया गया है, जिससे वे ट्रैफिक जाम, दुर्घटना या अन्य यातायात बाधाओं का तुरंत समाधान कर सकें।

जाम की सूचना इस नंबर पर दें

यातायात पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि शहर में कहीं भी जाम लगे तो यातायात हेल्पलाइन नंबर 94792 10632 पर सूचना दें। सूचना मिलते ही निकटतम दफ्ळ टीम मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारु करेगी।

वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कांबले, पुलिस उपायुक्त क्राइम स्मृतिक राजनाला, पुलिस उपायुक्त यातायात विवेक शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मुख्यालय अचर्ना झा सहित यातायात पुलिस के सभी थाना प्रभारी और अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। रायपुर पुलिस का यह प्रयास शहरवासियों को बेहतर, सुरक्षित और जाम-मुक्त यातायात सुविधा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

लालबाग पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को चंद घंटों में गिरफ्तार, आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

थाना लालबाग पुलिस ने दुष्कर्म और धमकी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

क्या है मामला

प्राथिर्या ने थाना लालबाग में शिकायत दर्ज कराई कि रमेश साहू, 48 वर्ष, निवासी ब्लॉक नंबर-14, अटल आवास, पेण्ड्री ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। साथ ही घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना लालबाग में अपराध क्रमांक 290/2026, धारा 64, 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के मार्गदर्शन में थाना लालबाग पुलिस ने तत्काल आरोपी की पतासाजी की।

आरोपी रमेश साहू पिता सुखराम साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर 11 जुलाई 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। थाना लालबाग पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना आगे जारी है।

नकटी सहित 6 गांवों की 1076 एकड़ जमीन बिल्डरों को सौंपने की तैयारी

पूर्व मंत्री मो. अकबर का आरोप - विवादित जमीन भी योजना में शामिल, 22 जुलाई अंतिम तिथि, डेवलपर को विकास और बिक्री का अधिकार

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मो. अकबर ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार नकटी गांव के विवाद को सुलझाने के बजाय वहां की जमीनों को निजी बिल्डरों को सौंपने की तैयारी कर रही है।

6 गांवों की 436 हेक्टेयर जमीन शामिल

पूर्व मंत्री ने कहा कि शासकीय दस्तावेजों के अनुसार नकटी, सेरीखेड़ी, मंदिर हसौद, रमचंडी, बरौंदा और रीको की कुल 436.01 हेक्टेयर यानी करीब 1076 एकड़ भूमि को नगर विकास योजना के नाम पर निजी हाथों में देने की योजना है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस प्रस्तावित योजना में नकटी गांव की कुछ जमीनें भी शामिल की गई हैं। अकबर ने सवाल उठाया कि सरकार स्पष्ट करे कि इस योजना में वह विवादित जमीन तो शामिल नहीं है जहां हाल में विध्वंस हुआ है।

डेवलपर को मिलेगा विकास और बिक्री का अधिकार

पूर्व मंत्री ने बताया कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा के दस्तावेजों के मुताबिक चयनित एजेंसी को सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, विद्युत जैसी आधारभूत संरचनाएं विकसित करने के बदले मिश्रित उपयोग यानी मिक्स यूज भूमि के विकास और उसके विक्रय का अधिकार दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जमीन सीधे नहीं बेची जा रही, बल्कि डेवलपर के माध्यम से बेची जाएगी। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2026 है।

पहले पीड़ितों को न्याय दें - मोहम्मद अकबर

मो. अकबर ने कहा कि नकटी गांव की जमीन को लेकर विवाद अभी सुलझा नहीं है। प्रभावित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हुआ है। विध्वंस के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार की प्राथमिकता मान्य व्यवस्थापन होना चाहिए। जब तक पीड़ित परिवारों को न्यायपूर्ण और सर्वसम्मत हक नहीं मिल जाता, तब तक जमीन को बिल्डरों को सौंपने की प्रक्रिया रोकी जाए।

फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लाखों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय में नौकरी का झांसा देकर की थी ठगी, आरोपी इमरान कादरी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने फर्जी नियुक्ति पत्र देकर युवाओं से लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने खुद को प्रभावशाली बताकर शासकीय विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था।

इस तरह की थी ठगी

थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी मोहम्मद इमरान कादरी, 37 वर्ष ने अभ्यथिर्यों को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में नियुक्ति कराने का विश्वास दिलाया। इसके लिए उसने फर्जी चयन सूची और फर्जी नियुक्ति पत्र भी उपलब्ध कराए और उनसे लाखों रुपये ऐंठ लिए। शिकायत मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर तकनीकी एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपी इमरान कादरी को गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पहले से दर्ज हैं 8 प्रकरण

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी इमरान कादरी के विरुद्ध पहले से जुआ और ठगी से संबंधित कुल 08 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। ये प्रकरण थाना सिविल लाइन, तेलीबांधा, सिमगा सहित अन्य थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं। आरोपी का वर्तमान पता परसतराई रोड, धरसींवा रायपुर बताया गया है। रायपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि नौकरी दिलाने या सरकारी भर्ती में चयन कराने के नाम पर किसी के बहकावे में आकर धनराशि का भुगतान न करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या ठगी की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या पुलिस हेल्पलाइन पर दें। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कहा है कि आर्थिक अपराधों और ठगी में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, मालवाहक ऑटो बरामद

रायपुर। राजधानी रायपुर में वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा गुढ़ियारी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी गया तीनपहिया मालवाहक ऑटो बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 1.20 लाख रुपये बताई गई है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से भी वाहन चोरी के तीन मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक, प्रार्थी पिंटू साहू ने गुढ़ियारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह रामनगर स्थित कबीर चौक सब्जी बाजार में सब्जी विक्रय का कार्य करता है। बाजार से सब्जियां लाने-ले जाने के लिए वह अपने तीनपहिया मालवाहक ऑटो (CG 04 MB 6240) का उपयोग करता था।

पुलगांव पुलिस की कार्रवाई : अवैध शराब बेचते आरोपी गिरफ्तार, 32 पौवा देशी शराब और नगदी बरामद, आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

अवैध शराब के खिलाफ दुर्ग पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। चौकी अंजोरा, थाना पुलगांव पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम धनोट में छापा मारकर अवैध रूप से देशी शराब बेच रहे आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

राजा तालाब के पास पकड़ा गया आरोपी

पुलिस के अनुसार 11 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम धनोट स्थित राजा तालाब के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से देशी शराब बेच रहा है। सूचना पर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक चंद्रशेखर सोनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा।

तलाशी लेने पर आरोपी के पास से बिक्री के लिए रखी 32 पौवा देशी मसाला शराब प्रत्येक 180 एमएल और 300 रुपये नगद बरामद हुई। जप्त शराब की अनुमानित कीमत 3,200 रुपये है। इस प्रकार कुल 3,500 रुपये की सामग्री जप्त की गई।

आबकारी एक्ट में कार्रवाई

गिरफ्तार आरोपी की पहचान धनेश बरैंया, 35 वर्ष, निवासी ग्राम धनोट के रूप में हुई। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई।

इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक चंद्रशेखर सोनी, आरक्षक डोमन देशमुख, कमल नारायण ठाकुर और आरक्षक झरना भूमिया की सराहनीय भूमिका रही।

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' के टीजर पर बॉबी देओल ने दी प्रतिक्रिया

सनी देओल की नई फिल्म 'बंटवारा 1947' का टीजर रिलीज हो गया है। फैंस इस टीजर को काफी पसंद कर रहे हैं। पहले इस फिल्म का नाम 'लाहौर 1947' रखा गया था। यह फिल्म 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं अब सनी के छोटे भाई और अभिनेता बॉबी देओल ने टीजर को लेकर अपनी राय पेश की है।

बॉबी देओल ने बरसाया प्यार

'बंटवारा 1947' के टीजर को देखने के बाद सनी देओल के छोटे भाई बॉबी देओल ने इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'आप सबसे अच्छे हैं, भैया।' बॉबी ने आगे लिखा, 'मैं इस फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित हूं और इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।' इसके साथ ही बॉबी ने 'बंटवारा 1947' की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं।

किस पर आधारित है फिल्म 'बंटवारा 1947'

सनी देओल की यह फिल्म असगर वजाहत के मशहूर नाटक 'जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ए नई' पर बनी है, जो 1947 भारत-पाकिस्तान विभाजन के दर्द की कहानी दिखाती है। फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान ने दिया है, जावेद अख्तर ने गाने लिखे हैं। 'बंटवारा 1947' में सनी देओल ने सिकंदर मिर्जा का किरदार निभाया है। इस फिल्म में सनी के अलावा प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, अभिमन्यु सिंह और करण देओल भी नजर आएंगे।

बॉबी देओल की फिल्म 'अल्फा' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की इस एक्शन फिल्म में बॉबी के साथ आलिया भट्ट और शरवरी मुख्य भूमिका में हैं। इसमें अनिल कपूर भी हैं और ऋतिक रोशन का कैमियो है।

पापा नवाजुद्दीन के साथ थिएटर डेब्यू करेंगी शोरा, 25 साल बाद फिर मंच पर लौटेंगे अभिनेता

नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। अभिनय उनकी रगों में दौड़ता है। फिल्मों के अलावा उन्होंने थिएटर में भी खूब शानदार काम किया है। अभिनय सफर की शुरुआत ही उन्होंने थिएटर से की थी। एक बार फिर करीब 25 साल बाद वे इस दुनिया में लौट रहे हैं। नाटक होगा 'नकाब'। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इसी नाटक के जरिए उनकी बेटी शोरा सिद्दीकी थिएटर डेब्यू करने जा रही हैं।

ढाई दशक बाद स्टेज पर दिखेंगे नवाजुद्दीन

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नाटक का पोस्टर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा करके खुद यह जानकारी दी है। करीब 25 साल बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने नाटक 'नकाब' के साथ एक बार फिर थिएटर में वापसी कर रहे हैं। यह सिर्फ उनकी वापसी नहीं, बल्कि अपनी जड़ों की ओर लौटने जैसा एक भावुक पल भी है। इसे लेकर नवाजुद्दीन सिद्दकी बेहद उत्साहित हैं।

मैं अपने घर लौट आया हूं

थिएटर में कमबैक पर नवाजुद्दीन ने कहा, 'थिएटर ही वह जगह है, जहां मैंने खुद को एक अभिनेता के रूप में पहचाना। यहीं मैंने ईमानदारी, धैर्य और सिर्फ अपनी कला के भरोसे दर्शकों के सामने खड़े होने का साहस सीखा। करीब 25 साल बाद फिर से मंच पर लौटना ऐसा लग रहा है, जैसे मैं अपने घर लौट आया हूं। इस वापसी को और भी खास बनाती है एक और बात।

बेटी के डेब्यू पर जताई खुशी

इस नाटक में नवाजुद्दीन पहली बार अपनी बेटी के साथ मंच साझा करेंगे। नाटक से शोरा के अभिनय सफर की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा, 'इस सफर को और भी भावुक बनाने वाली बात यह है कि मैं अपनी बेटी के साथ मंच साझा करूंगा। एक पिता के तौर पर इससे बड़ा गर्व का पल मेरे लिए नहीं हो सकता। मुझे बस उम्मीद है कि दर्शक उसे भी वही प्यार और अपनापन देंगे, जो उन्होंने हमेशा मुझे दिया है'। 'नकाब' एक ऐसी कहानी है, जिसमें सस्पेंस, ह्यूमर और कई सरप्राइज हैं।

'अलायंस' से सलमान के भाई वाली छवि बदलेंगे सोहेल खान?

सोहेल खान शो 'अलायंस' में शिरकत करने वाले हैं। वे बतौर वाइल्ड कार्ड प्रतिभागी एंट्री लेंगे। सोहेल बतौर जज कई रियलिटी शो में नजर आ चुके हैं। मगर, यह पहला मौका है, जब वे बतौर प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। सोहेल खान ने शो को लेकर हाल ही में बात करते हुए कहा कि यहां बड़े भाई सलमान खान का स्टारडम काम नहीं आएगा। इस शो में रणनीति के साथ रहना होगा।

शो 'अलायंस' को कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं। यहां कई सेलिब्रिटीज बतौर प्रतिभागी शामिल हुए हैं। इस शो में जाने से पहले सोहेल खान का इरादा साफ है कि वे यहां अपनी खुद की पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। सलमान खान के भाई वाली इमेज को वे बदल देना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले सोहेल की 'अलांयस' से जुड़ने की खबरें सामने आई थीं। अब खुद सोहेल खान ने इसकी पुष्टि कर दी है।

बदलेंगे 'सलमान के भाई की छवि'

सोहेल खान बतौर डायरेक्टर और एक्टर फिल्मों में काम कर चुके हैं। हालांकि, बतौर अभिनेता उन्हें खास पहचान नहीं मिली। आज भी परिचय देते वक्त लोग उन्हें 'सलमान खान का भाई' कहते हैं। हाल ही में 'अलायंस' में जाने से पहले सोहेल ने मीडिया से बातचीत की और शो में अपनी योजना के बारे में बात की। साथ ही अपनी पहचान पर बात की। एचटी के मुताबिक, सोहेल का कहना है कि वे शो के जरिए अपनी सलमान के भाई वाली छवि बदलना चाहेंगे। सोहेल खान का कहना है, 'शो में कोई परिवार का नाम नहीं है, जिस पर मैं टिक सकूं। इंडस्ट्री की भी कोई जोर-जबर्दस्ती नहीं है। यहां सिर्फ मैं हूं। मेरा दिमाग है और मैं गेम कैसे खेलता हूं? यह है। अगर लोग जाते वक्त मेरा वह पक्ष देखें जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, तो यह बहुत अच्छा होगा। सिर्फ इसी वजह से मैं इस शो में आया हूं। सोहेल खान ने 'अलायंस' और 'बिग बॉस' के बीच के फर्क पर भी बात की। उन्होंने कहा कि 'बिग बॉस' काफी एनर्जी है।

एक्ट्रेस माही विज ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक

अभिनेत्री माही विज तलाक के बाद पूरी तरह से अपने काम में डूबी हुई हैं। इसके साथ ही वह एक सिंगल मदर की जिम्मेदारियां को भी निभा रही हैं। इसी बीच मंगलवार को एक्ट्रेस ने एक इंस्टा स्टोरी शेयर कर अपने फैंस को चौंकाया। इस स्टोरी में माही ने बताया कि वह सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हैं। हालांकि, कुछ वक्त बाद उन्होंने इसे डिलीट कर दिया। माही ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हूं, पता नहीं कब तक, जब तक काम से जुड़ी कोई चीज पोस्ट न करनी हो। दुआ में याद रखना।'

तलाक के बाद बेटी संग रहती हैं एक्ट्रेस

माही विज और उनके पति जय भानुशाली की शादी 15 साल तक चली। मगर आपसी मदभेदों के कारण कपल ने इस साल की शुरुआत में ही तलाक की घोषणा की थी। कपल के तीन बच्चे थे। तारा (उनकी बायोलॉजिकल बेटी), खुशी और राजवीर (जिन्हें उन्होंने गोद लिया है)। फिलहाल माही अपनी बेटी तारा संग कई बार सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर करती देखी जाती थीं।

रवीना टंडन ने बॉलीवुड में अभिनेत्रियों की घटती भूमिका का उठाया मुद्दा

रवीना टंडन की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई कर रही है। यह एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म है। इसी बीच रवीना ने बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्मों में हीरोइनों की भूमिकाओं को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रवीना टंडन ने 90 के दशक में 'अंदाज अपना अपना' और 'दूल्हे राजा' जैसी कई शानदार कॉमेडी फिल्मों में काम किया था। पीटीआई से बातचीत के दौरान, रवीना ने कहा कि उस दौर में अभिनेत्रियों को खुलकर कॉमेडी करने का मौका मिलता था। आजकल की कॉमेडी फिल्में बहुत ज्यादा बंधी-बंधाई होती हैं या फिर उनमें बहुत सारे कलाकार होते हैं। इस वजह से हीरोइनों के हिस्से में मजेदार और हंसाने वाले सीन बहुत कम आते हैं।

श्रीदेवी और जूही चावला की तारीफ

रवीना ने 'मिस्टर इंडिया' और 'चालबाज' जैसी फिल्मों से साबित किया कि एक खूबसूरत हीरोइन भी बेहतरीन कॉमेडी और हाव-भाव से लोगों को हंसा सकती है। इसके साथ ही रवीना ने जूही चावला की कॉमिक टाइमिंग और गीता बाली और मधुबाला जैसी पुरानी अभिनेत्रियों के मजाकिया अंदाज की भी तारीफ की। रवीना ने कहा, 'आजकल की अभिनेत्रियां बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन फिल्मों की स्क्रिप्ट उन्हें सिर्फ सुंदर दिखने तक सीमित कर देती है। हमें ऐसे लेखकों की जरूरत है, जो महिलाओं के लिए मजेदार और हंसाने वाले किरदार लिखें, बिना यह सोचे कि उन्हें हर वक्त परफेक्ट दिखना है।'

बड़े पर्दे पर पहली बार बनेगी अली फजल और ऋचा चड्ढा की जोड़ी, ऐसी होगी फिल्म की कहानी

बॉलीवुड कपल अली फजल और ऋचा चड्ढा पहली बार किसी फिल्म में एक-दूसरे के अपोजिट नजर आएंगे। यानी पहली बार ये रियल लाइफ जोड़ी बड़े पर्दे पर भी एक जोड़ी के रूप में नजर आएगी। हालांकि, दोनों ने पहले 'फुकरे' फ्रैंचाइजी में साथ काम किया है, लेकिन स्क्रीन पर उन्हें कभी एक-दूसरे के अपोजिट कास्ट नहीं किया गया। एक्टर-राइटर-डायरेक्टर शशि वर्मा की आने वाली फिल्म में कपल साथ नजर आएगा। कपल ने इसको लेकर अपना उत्साह भी जाहिर किया है।

ऐसी होगी फिल्म की कहानी

अली और ऋचा आखिरकार पहली बार एक साथ एक बिना नाम वाली सिचुएशनल कॉमेडी फिल्म में काम करने जा रहे हैं, जिसे सीनवर्क प्रोडक्शंस और गिरिराज प्रोडक्शंस बना रहे हैं। इनके अलावा फिल्म में कुमुद मिश्रा भी नजर आएंगे। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी पर आधारित इस फिल्म को एक्टर-राइटर-डायरेक्टर शशि वर्मा डायरेक्ट करेंगे। शशि वर्मा पहले 'बाला', 'गुंजन सक्सेना' और 'कटहल' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं और उन्होंने 'AK47' और 'मुर्गा ट्रॉफी' जैसी फिल्में लिखी हैं। हालांकि, अभी फिल्म का टाइटल सामने नहीं आया है। फिल्म की शूटिंग 2026 के दूसरे हिस्से में शुरू होगी और इसे अप्रैल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं

इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए अली फजल ने कहा, 'मेरा हमेशा से मानना रहा है कि सबसे अच्छी कॉमेडी ईमानदार किरदारों और असल लगने वाली स्थितियों से बनती है। जैसे ही मैंने यह स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे पता चल गया कि इसमें कुछ खास है। ऋचा के साथ स्क्रीन पर एक बिल्कुल नया तालमेल आजमाना भी रोमांचक है। मैं सच में उस चीज का इंतज़ार कर रहा हूं जो हम साथ मिलकर बनाएंगे। शशि सर के काम को मैं हमेशा से फॉलो करता रहा हूं और उनके साथ काम करना मेरी हमेशा से इच्छा रही है। इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का यह भी एक बड़ा कारण है।'

कहानी की सादगी नेमुझे खींचा

वहीं ऋचा चड्ढा ने फिल्म को लेकर अपना उत्साह जताते हुए कहा, 'इस कहानी की सादगी और असलियत ने मुझे अपनी ओर खींचा। यह मजेदार और इमोशनल है और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है, साथ ही इसमें समाज पर एक बेहतरीन टिप्पणी भी है। अली और मैंने पहले भी साथ काम किया है, लेकिन कभी ऐसा नहीं किया। मैं सच में उत्साहित हूं कि दर्शक हमें एक बिल्कुल नए अंदाज में साथ देखेंगे। इस कहानी ने मुझे दिल्ली के यमुना पार में बिताए अपने स्कूल के दिनों की याद दिला दी। अली एक बेहतरीन एक्टर हैं। हमें पहले कभी इस तरह साथ काम करने का मौका नहीं मिला। इससे पहले हमने 'फुकरे' में काम किया था, जहां हमारे किरदार अलग-अलग थे।'

राजनांदगांव पुलिस को तकनीक की ताकत : 150 विवेचकों को मिले स्मार्ट मोबाइल

एसपी अंकिता शर्मा ने किया वितरण, कहा – अब डिजिटल साक्ष्य से होगी तेज और पारदर्शी विवेचना

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजनांदगांव पुलिस को तकनीक से जोड़ा गया है। पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा उपलब्ध कराए गए 150 स्मार्ट मोबाइल पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) के हाथों जिले के विवेचकों को वितरित किए गए।

डिजिटल होगी विवेचना

पुलिस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एसपी अंकिता शर्मा ने कहा कि नए कानूनों के लागू होने के बाद विवेचना में तकनीक की भूमिका और बढ़ गई है। इन स्मार्ट मोबाइलों के जरिए विवेचक घटनास्थल से डिजिटल साक्ष्य संकलन, फोटो-वीडियो दस्तावेजीकरण, ऑनलाइन रिपोर्टिंग और विभिन्न पुलिस एप्लिकेशन का उपयोग कर सकेंगे।

उन्होंने कहा, "इससे विवेचना अधिक पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध बनेगी। विवेचक तकनीक का उपयोग कर गुणवत्तापूर्ण और वैज्ञानिक विवेचना सुनिश्चित करेंगे।"

एसपी ने सभी विवेचकों को निर्देश दिए कि मोबाइल का उपयोग केवल शासकीय कार्यों में किया जाए। उन्होंने डिजिटल साक्ष्यों के समुचित संकलन और उत्कृष्ट विवेचना पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इससे आमजन को त्वरित और प्रभावी न्याय मिल सकेगा।

पुलिसकर्मियों ने जताया आभार

कार्यक्रम में नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन और उप पुलिस अधीक्षक के.पी. मरकाम सहित सभी विवेचक मौजूद रहे। विवेचकों ने पुलिस मुख्यालय और एसपी अंकिता शर्मा के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह मोबाइल नए कानूनों के अनुरूप विवेचना को सरल, तेज और प्रभावी बनाने में मददगार साबित होंगे।

राजनांदगांव पुलिस ने कहा है कि वह नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और तकनीक आधारित विवेचना के जरिए नागरिकों को बेहतर पुलिस सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

खास खबर

कल से 18 जुलाई तक जिले में चलेगा विशेष एचपीवी टीकाकरण अभियान

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

14 वर्ष से अधिक एवं 15 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के लिए विशेष अभियान

गर्भाशय कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बालिकाओं को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कबीरधाम जिले में 13 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक विशेष एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के दौरान 14 वर्ष से अधिक एवं 15 वर्ष से कम आयु की पात्र बालिकाओं को निःशुल्क एचपीवी वैक्सीन लगाई जाएगी।

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. सलिल मिश्रा ने बताया कि जिले में एचपीवी टीकाकरण की शुरुआत 16 मार्च 2026 को जिला चिकित्सालय से की गई थी। वर्तमान में जिला चिकित्सालय सहित जिले के सभी 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा कोल्ड चेन प्वाइंट वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित रूप से रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक टीकाकरण किया जा रहा है। विशेष अभियान के दौरान भी पात्र बालिकाओं का टीकाकरण निर्धारित केंद्रों पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) संक्रमण गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर का प्रमुख कारण है। विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष लगभग 74 हजार से 77 हजार महिलाओं की मृत्यु गर्भाशय कैंसर के कारण होती है, जिनमें लगभग एक-तिहाई मौतें भारत में होती हैं। ऐसे में समय पर लगाया गया एचपीवी टीका इस गंभीर बीमारी से बचाव का प्रभावी माध्यम है।

टीकाकरण के लिए बालिका की आयु का सत्यापन आधार कार्ड अथवा जन्म प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाएगा। एचपीवी वैक्सीन 0.5 एमएल की एकल (सिंगल) डोज के रूप में बाईं ऊपरी बांह में लगाई जाएगी। गर्भावस्था की स्थिति में टीका नहीं लगाया जाएगा तथा लाभार्थी को खाली पेट टीका नहीं लगवाना चाहिए। टीकाकरण के बाद तजर्नी उंगली पर मार्किंग की जाएगी, टीकाकरण कार्ड प्रदान किया जाएगा तथा किसी भी संभावित सामान्य प्रतिक्रिया की निगरानी के लिए लाभार्थी को 30 मिनट तक केंद्र पर रुकना होगा। टीकाकरण से पूर्व पालक की सहमति भी ली जाएगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डी.के. तुरे ने जिले के सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी 14 वर्ष से अधिक एवं 15 वर्ष से कम आयु की पात्र बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण अवश्य कराएं। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 1177 बालिकाओं को एचपीवी का टीका लगाया जा चुका है तथा टीकाकरण के बाद किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। इससे स्पष्ट है कि यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित एवं प्रभावी है। उन्होंने यह भी बताया कि यही वैक्सीन निजी अस्पतालों में लगभग 4,000 से 6,000 रुपये की लागत से उपलब्ध है, जबकि शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में यह पात्र बालिकाओं को निःशुल्क प्रदान की जा रही है। उन्होंने सभी पालकों से विशेष टीकाकरण अभियान का लाभ उठाकर अपनी बेटियों को गर्भाशय कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने की अपील की।

खनिज विभाग की कार्रवाई : चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते 2 हाईवा वाहन जप्त

थाना सुकुलदैहान को सुपुर्द, अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

राजनांदगांव। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा जिले में अवैध खनन और परिवहन पर लगातार कार्रवाईकी जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को खनिज विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण कर चूना पत्थर गिट्टी का अवैध परिवहन करने पर 2 हाईवा वाहनों को जप्त किया। खनिज टीम ने करियाटोला, कोहका, मोहारा, ऑक्सीजोन, डुमरडीहकला, चवेली, सुकुलदैहान सहित अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान अवैध परिवहन करते पाए जाने पर कार्रवाई की गई।

ये वाहन हुए जप्त : हाईवा क्रमांक सीजी 08 एवी 7848 – स्वामी योगेश देवांगन, चालक वाल्मिकी साहू, हाईवा क्रमांक एमएच 35 एजे 9437 – स्वामी कन्हैया लाल अग्रवाल, चालक विजय लांजेवार दोनों वाहनों को जप्त कर थाना सुकुलदैहान को सुपुर्द कर दिया गया है। प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खनिज अधिकारी ने बताया कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खन, परिवहन और भंडारण पर रोकथाम के लिए लगातार गश्त और निगरानी की जा रही है।

"बाजार खुलने से पहले पूरी सफाई हो, कचरा तत्काल उठे" –आयुक्त मरकाम ने दिए निर्देश

नगर निगम आयुक्त जीआर मरकाम का पहला वार्ड विजिट

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

नवागत नगर निगम आयुक्त जीआर मरकाम ने गुरुवार को अपना पहला वार्ड विजिट किया। उन्होंने गोल बाजार, जय स्तंभ चौक, सिनेमा लाइन, गंज चौक और भरकापारा एसएलआरएम सेंटर का निरीक्षण कर शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया।

बाजार क्षेत्र में सफाई पर जोर

आयुक्त ने गोल बाजार में पैदल भ्रमण कर स्वास्थ्य अमले को निर्देश दिए कि बाजार लगने से पहले पूरे क्षेत्र की समुचित सफाई की जाए। जय स्तंभ चौक के आसपास प्रतिदिन अच्छी सफाई करने और किसी भी तरह का कचरा या सामान न रखने के निर्देश दिए। ट्रांसफार्मर के पास कपड़ा और कूड़ा देख उन्होंने उसे तत्काल हटवाया। सिनेमा लाइन और गंज लाइन में दुकानें खुलने से पहले सड़कों और नालियों की सफाई कर कचरा उठाने को कहा।

नाली के पास खाली जमीन में मलवा पड़े होने पर उन्होंने उन स्थानों की सफाई कर 1 फीट ऊंची दीवार बनवाने के निर्देश दिए, ताकि वहां कचरा न डाला जा सके। गंज चौक के नाले की भी समुचित सफाई कराने को कहा ताकि बारिश का पानी आसानी से निकल सके।

एसएलआरएम सेंटर का निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान आयुक्त मरकाम ने भरकापारा एसएलआरएम सेंटर पहुंचकर कचरा निपटान प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र प्रभारी को समय सीमा में कचरे का उचित निपटान और केंद्र में साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने कबाड़ सामग्री को जल्द बेचने, गीला-सूखा कचरा अलग-अलग लेने और डोर टू डोर कचरा संग्रहण के समय डस्टबिन निकालकर रखने के लिए लोगों को समझाइश देने को कहा। सेंटर के सामने रखी लो-बेड ट्रॉली को शेड के अंदर रखने, बोर के पंप सुधरवाने और पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी राजेश मिश्रा, स्वच्छता निरीक्षक दीपक श्रीवास्तव सहित स्वास्थ्य अमला उपस्थित था।

---

17 अगस्त को पाटन से टोलाघाट के लिए निकलेगी भव्य कांवर यात्रा

एक मुट्ठी अन्नदान से बनेगा महाप्रसाद, आयोजन को लेकर बैठक में बनी रूपरेखा

नई दृष्टिबिंदु / पाटन

बोल बम कांवर यात्रा समिति, पाटन की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को रेस्ट हाउस में समिति के संयोजक जितेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सावन के तीसरे सोमवार 17 अगस्त को प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पाटन से टोलाघाट तक भव्य एवं विशाल कांवर यात्रा निकाली जाएगी।

आस्था और सेवा का प्रतीक है कांवर यात्रा : बैठक में यात्रा को अधिक भव्य, सुव्यवस्थित और श्रद्धामय स्वरूप देने के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस बार भी भगवान शंकर के नाम पर शिवभक्तों से प्राप्त एक मुट्ठी अन्नदान से महाप्रसाद तैयार किया जाएगा।

संयोजक जितेन्द्र वर्मा ने कहा कि कांवर यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, आस्था, अनुशासन, सेवा और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष हजारों शिवभक्त "बोल बम" के जयघोष के साथ भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए इस यात्रा में शामिल होते हैं। इस बार यात्रा पाटन के ओग्गर तालाब में विराजमान भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर टोलाघाट के लिए रवाना होगी।

सभी व्यवस्थाओं पर हुई चर्चा : बैठक में यात्रा मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सहायता, पेयजल एवं भोजन व्यवस्था, विश्राम स्थल, यातायात समन्वय, स्वच्छता, प्रचार-प्रसार और स्वयंसेवकों की जिम्मेदारियों सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा कर दायित्व तय किए गए।

बैठक के अंत में जितेन्द्र वर्मा ने पाटन क्षेत्र के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठनों, युवा मंडलों, महिला समूहों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारी बंधुओं और शिवभक्तों से अधिक से अधिक संख्या में यात्रा में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन किसी एक व्यक्ति या समिति का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की आस्था और सामूहिक सहभागिता का महापर्व है।

समिति ने सभी श्रद्धालुओं से 17 अगस्त को पाटन से टोलाघाट तक निकलने वाली इस भव्य कांवर यात्रा में सहभागी बनकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है। बैठक में दिलीप साहू, योगेश भाले, कमलेश वर्मा, रानी केशव बंछोर, कमलेश चंद्राकर, धर्मेन्द्र सिन्हा, ज्योतिप्रकाश साहू, पी. एन. दुबे, राकेश पाण्डेय, निशा सोनी, उनिका वर्मा, रश्मि कुर्रे, किरण वर्मा, गीतेश्वरी सपहा, हेमलता पटेल, चंद्रिका साहू सहित बड़ी संख्या में समिति के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे।

जिला अस्पताल सहित पांच प्रमुख खाद्य प्रतिष्ठानों का ईट राइट कैंपस व हाइजीन रेटिंग ऑडिट संपन्न

एफएसएसएआई के ईट राइट इंडिया अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का किया गया विस्तृत मूल्यांकन

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के ईट राइट इंडिया अभियान के अंतर्गत जिले में सुरक्षित एवं स्वच्छ खाद्य व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला अस्पताल कबीरधाम का ईट राइट कैंपस ऑडिट तथा जिले के पांच प्रमुख खाद्य प्रतिष्ठानों का हाइजीन रेटिंग ऑडिट किया गया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के समन्वय में एफएसएसएआई द्वारा अधिकृत थर्ड पार्टी ऑडिटर एवं विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में जिला अस्पताल कबीरधाम का निरीक्षण किया गया। ऑडिट के दौरान अस्पताल की रसोई, भोजन निर्माण एवं वितरण व्यवस्था, खाद्य सामग्री का सुरक्षित भंडारण, पेयजल व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ-सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन, कीट नियंत्रण व्यवस्था तथा खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों के अनुपालन का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक सुधारात्मक सुझाव भी दिए गए।

इसके साथ ही जिले के पांच प्रमुख खाद्य प्रतिष्ठानों का भी हाइजीन रेटिंग ऑडिट किया गया। इनमें श्रीधर चैधरी स्वीट्स एकता चैक, कवर्धा, डोमिनोज पिज्जा रायपुर रोड, कवर्धा, नटराज होटल एंड एडवेंचर रिसॉर्ट्स (चिल्फी), गरुड़ा इन चिल्फी, बोड़ला तथा जोहार एथनिक रिसॉर्ट सरोधा दादर, चिल्फी शामिल हैं। ऑडिट के दौरान इन प्रतिष्ठानों में रसोई की स्वच्छता, खाद्य पदार्थों का सुरक्षित भंडारण, कच्चे एवं पके खाद्य पदार्थों का पृथक्करण, तापमान नियंत्रण, खाद्य हैंडलर्स की व्यक्तिगत स्वच्छता, मेडिकल फिटनेस, खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, कीट नियंत्रण व्यवस्था तथा एफएसएसएआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन का विस्तृत परीक्षण किया गया। साथ ही खाद्य कारोबारियों एवं कमर्चारियों को सुरक्षित एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन एवं सुधारात्मक सुझाव भी प्रदान किए गए।

अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता सामग्री का वितरण किया गया तथा खाद्य कारोबारियों को स्वच्छ परिसर, सुरक्षित भोजन और स्वस्थ उपभोक्ता की अवधारणा को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया कि ईट राइट इंडिया अभियान का उद्देश्य केवल निरीक्षण एवं मूल्यांकन तक सीमित नहीं है, बल्कि खाद्य कारोबारियों में खाद्य सुरक्षा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना तथा आम नागरिकों को सुरक्षित, पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। विभाग द्वारा जिले के अस्पतालों, होटलों, रेस्टोरेंटों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य सार्वजनिक भोजनालयों में इस प्रकार के ऑडिट एवं जनजागरूकता कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे।

कार्यक्रम महापौर मधुसूदन यादव ने किया भूमिपूजन, कहा- समय सीमा में होगा कार्य पूर्ण

हल्दी में 53 लाख की लागत से बनेंगी सीमेंट कांक्रीट सड़कें और नालियां

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

नगर निगम द्वारा शासन से स्वीकृत राशि से वार्डों में विकास कार्यों की कड़ी में गुरुवार को वार्ड क्रमांक 51 हल्दी में 53 लाख रुपये की लागत से सीमेंट कांक्रीट रोड और नाली निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। महापौर मधुसूदन यादव ने महापौर परिषद के प्रभारी सदस्य सावन वर्मा, सुनील साहू, आलोक श्रुति, डीलेश्वर साहू, वार्ड पार्षद चंद्रकृत साहू, वरिष्ठ पार्षद शिव वर्मा सहित अन्य पार्षदों और वार्डवासियों की उपस्थिति में श्रीफल फोड़कर एवं गैती चलाकर कार्य का शुभारंभ किया।

आवागमन और जल निकासी में होगी सुविधा

भूमिपूजन अवसर पर महापौर यादव ने कहा कि शासन ने अधोसंरचना और अधोसंरचना उपकर निधि के तहत नगर निगम को विकास कार्यों की स्वीकृति दी है। विधायक डॉ. रमन सिंह और सांसद संतोष पाण्डे की अनुशंसा पर उनकी निधि से भी विभिन्न वार्डों में कार्य कराए जा रहे हैं।

इसी कड़ी में हल्दी में 50 लाख से अधिक की राशि से रोड और नाली निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "सड़क बनने से आवागमन सुगम होगा और नाली निर्माण से घरों का पानी व बारिश का पानी आसानी से निकल सकेगा। कार्य जल्द शुरू कर गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा कराया जाएगा, ताकि हल्दीवासियों को इसका लाभ मिल सके।"

कार्यक्रम के पूर्व वार्डवासियों संजय साहू, अनिता यादव, दुर्गा साहू, प्रमिला साहू, टिकेश्वरी साहू सहित अन्य ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। इस अवसर पर सहायक अभियंता श्रीमती ज्योति साहू सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित थे।

नाबार्ड ने ग्रामीण महिला को स्वरोजगार के लिए दिया मुवेबल कार्ट

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

सोमनी की अनोखी बाई को निशुल्क मिला चलित ठेला और स्टार्टअप किट

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) छत्तीसगढ़ के वित्तीय सहयोग से संस्था प्रतिभा महिला एवं बाल विकास समिति, राजनांदगांव द्वारा राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सोमनी में गरीब महिला को स्वरोजगार के लिए मुवेबल कार्ट प्रदान किया गया। ग्राम सोमनी के विद्या स्वयं सहायता समूह की महिला अनोखी बाई को यह चलित ठेला निशुल्क दिया गया है। नाबार्ड द्वारा प्रायोजित मुवेबल कार्ट का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और उद्यमियों को आजीविका एवं स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से छोटे कारोबारियों के उत्पादों की पहुंच बाजारों तक बढ़ती है और उनकी आय में वृद्धि होती है।

किराए के कार्ट से मिली मुक्ति : अनोखी बाई के पास पहले अपना कोई कार्ट नहीं था। वह किराए के ठेले पर अंडा और फास्ट फूड का व्यवसाय करती थीं। नाबार्ड द्वारा प्रतिभा महिला एवं बाल विकास समिति के माध्यम से उन्हें बेहतरीन गुणवत्ता का मुवेबल कार्ट के साथ-साथ स्टार्टअप किट भी निशुल्क उपलब्ध कराई गई है। विद्या स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने खुशी जताते हुए कहा कि नाबार्ड की इस पहल से उन्हें स्थायी व्यापार मंच मिला है जिससे बिक्री बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

सीजीएम ने किया उद्घाटन : ग्राम सोमनी में मुवेबल कार्ट का उद्घाटन 7 जुलाई को नाबार्ड छत्तीसगढ़ के मुख्य महाप्रबंधक डी.के. गवली के करकमलों से किया गया। उद्घाटन समारोह में नाबार्ड छत्तीसगढ़ के सहायक प्रबंधक अनंत शिंदे, नाबार्ड राजनांदगांव के जिला विकास प्रबंधक मनोज कुमार नायक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के मुख्य कायर्पालन अधिकारी सुधीर सोनी, प्रतिभा महिला एवं बाल विकास समिति के अध्यक्ष एकलव्य तिवारी, संस्था जनकल्याण सामाजिक संस्थान के अध्यक्ष योगेन्द्र प्रताप सिंह और विद्या स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रहीं।

अब बेटी के जन्म पर 21 हजार की एफडी, 18 साल के बाद मिलेंगे करीब एक लाख

भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए विधायक रिकेश का एक और बड़ा तोहफा

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

विधायक रिकेश सेन ने भारतीय जनता पार्टी के वैशाली नगर विधानसभा के रहवासी कार्यकर्ताओं के सामाजिक और पारिवारिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की है। स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़ी आठ विशेष योजनाओं की घोषणा के बाद अब उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए कन्या भविष्य सुरक्षा योजना का ऐलान किया है, जो 10 अगस्त 2026 से लागू होगी।

विधायक श्री सेन ने बताया कि 10 अगस्त 2026 के बाद वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं के घर यदि कन्या का जन्म होता है, तो उस नवजात बेटी के नाम पर 21,000 की फिक्स डिपॉजिट (एफडी) कराई जाएगी। यह राशि 18 वर्ष की अवधि पूरी होने पर परिपक्व होगी और तब बेटी को करीब 1 लाख रूपये की राशि प्राप्त होगी। यह आर्थिक सहयोग उसकी उच्च शिक्षा, आत्मनिर्भरता या विवाह जैसे महत्वपूर्ण पड़ावों पर परिवार के लिए संबल बनेगा।

श्री सेन ने कहा कि बेटी केवल परिवार की नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होती है। उनका प्रयास है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों की बेटियों का भविष्य आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित और सशक्त बने।

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब विधायक रिकेश सेन पहले ही भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण से जुड़ी आठ कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर चुके हैं, जिनका लाभ भी 10 अगस्त 2026 से मिलना प्रारंभ होगा। इन योजनाओं का उद्देश्य वर्षों तक संगठन के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

जनसेवा के केंद्र में स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान

विधायक रिकेश सेन का जनप्रतिनिधित्व केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहा है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन की पहुंच तक लाने के उद्देश्य से कई अभिनव योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ हजारों परिवारों को मिल रहा है।

1 मई 2026 से संचालित मां-शिशु सुरक्षा कवच योजना के माध्यम से जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को सुरक्षा और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा उनकी पहल पर क्षेत्र में पावर चश्मा वितरण, निःशुल्क एक्स-रे, सोनोग्राफी, डायलिसिस सुविधा तथा मोतियाबिंद ऑपरेशन जैसी स्वास्थ्य सेवाएं भी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। इन योजनाओं ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के इलाज का बोझ कम करने के साथ हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है।

सेवा आधारित राजनीति की नई पहचान

लगातार जनहित और कार्यकर्ता हित की योजनाओं के माध्यम से विधायक रिकेश सेन ने यह संदेश दिया है कि जनप्रतिनिधि का दायित्व केवल विकास कार्यों तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य को मजबूत करना भी है।

स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, मातृ-शिशु कल्याण और अब बेटी के भविष्य को आर्थिक संबल देने वाली एफडी योजना उनके उस दूरदर्शी विजन का प्रमाण है, जिसमें संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं और विधानसभा की जनता के जीवन को अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाने का स्पष्ट संकल्प दिखाई देता है।

भिलाई चेंबर ने नवनियुक्त आयुक्त सुरुचि सिंह से की सौजन्य मुलाकात

जल्द पदभार ग्रहण कर विकास कार्यों को गति देने का किया अनुरोध

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

नगर पालिका निगम भिलाई की नवनियुक्त आयुक्त सुरुचि सिंह से भिलाई चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान चेंबर के प्रतिनिधियों ने सुरुचि सिंह का स्वागत करते हुए उनसे जल्द से जल्द भिलाई में पदभार ग्रहण करने का अनुरोध किया, ताकि शहर के रुके हुए विकास कार्यों को नई गति मिल सके।

चेंबर के साथियों ने कहा कि भिलाई में कई बुनियादी और विकास से जुड़े काम लंबे समय से लंबित हैं। आयुक्त के शीघ्र पदभार ग्रहण करने से प्रशासनिक प्रक्रिया तेज होगी और शहर के व्यापारियों एवं आम नागरिकों को राहत मिलेगी। नवनियुक्त आयुक्त सुरुचि सिंह ने चेंबर के सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और शहर के समग्र विकास के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर काम करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर चेंबर के वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।

चित्रकोट में रील बनाने के लिए महिला सर्किट हाउस की छत पर चढ़ी, वीडियो वायरल : जगदलपुर। बस्तर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चित्रकोट में एक महिला द्वारा जान जोखिम में डालने का मामला सामने आया है। महिला ने सुरक्षा नियमों को दरकिनार करते हुए सर्किट हाउस की छत पर चढ़कर वीडियो बनाया और उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सर्किट हाउस की छत पर बनाए गए कई वीडियो शेयर किए हैं। इनमें से एक वीडियो में वह छत पर खड़े होकर नाचते हुए रील बनाती नजर आ रही है।

कीर्तीशेष सम्मान 2026 से सम्मानित होंगी पंडवानी गायिका डॉ. तीजन बाई

14 जुलाई को गनियारी में परिवार को दिया जाएगा मरणोपरांत सम्मान

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

स्वर्गीय राम मोहनन जी की स्मृति में अखिल भारतीय उत्कृष्ट बहुउद्देशीय संस्था द्वारा दिया जाने वाला कीर्तीशेष सम्मान 2026 इस वर्ष भारत की प्रख्यात पंडवानी गायिका डॉ. तीजन बाई को मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा।

संस्था द्वारा 4 जुलाई 2026 को लिए गए निर्णय के अनुसार यह सम्मान डॉ. तीजन बाई को उनकी कला साधना और तपस्या के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में दिया जाना था। लेकिन 5 जुलाई 2026 को सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका डॉ. तीजन बाई के निधन के बाद अब यह सम्मान मरणोपरांत उनके परिवार को भेंट किया जाएगा।

14 जुलाई को गनियारी में सम्मान समारोह

कीर्तीशेष सम्मान समारोह 14 जुलाई 2026 को डॉ. तीजन बाई के गृहग्राम गनियारी में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर सम्मान स्वरूप नगद धनराशि एवं सम्मान पत्र उनके परिजनों को प्रदान किए जाएंगे। संस्था की अध्यक्ष श्रीमती शानू मोहनन ने बताया कि डॉ. तीजन बाई ने अपनी कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को विश्वभर में पहचान दिलाई। उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा।

फायर एवं सेफ्टी प्रशिक्षण में प्रवेश प्रारंभ

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	क्र.	पाठ्यक्रम का नाम
1.	फायर टेक्नोलॉजी एण्ड इंडस्ट्रियल सेफ्टी	5.	पी. जी. कोर्स व्यावसायिक सेफ्टी, स्वास्थ्य व पर्यावरण मैनेजमेंट सिस्टम
2.	इंडस्ट्रियल सेफ्टी / पी. जी. इंडस्ट्रियल सेफ्टी	6.	हैल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर
3.	बी.एस.सी. इन फायर सेफ्टी	7.	सब- फायर ऑफिसर
4.	पी. जी. कोर्स फायर एवं इंडस्ट्रियल सेफ्टी	8.	सर्टिफिकेट इन फायरमैन-इंडस्ट्रियल सेफ्टी

(An Authorized Training Centre of AEERO)

फायर सेफ्टी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट

(मान्यता प्राप्त निजी प्रशिक्षण संस्थान)

कैंपस :- इंदिरा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़

ADMISSION HELPLINE: 7697212782

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100